

वर्ष-23 अंक- 33
पृष्ठ 8
रविवार
18 अक्टूबर 2026
प्रातः संस्करण
हिन्दी दैनिक
प्रयागराज
मूल्य-1.00

प्रयागराज से प्रकाशित

Email : shaharsamta@gmail.com

Website : https://Shaharsamta.com

सम्पादक-उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विविध- कहीं आप भी तो नहीं दे रहे...

विचार- भारत की ताकत एकरूपता नहीं...

खेल- मुंबई इंडियंस के साथ खत्म हुआ 10...

लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह, योगी बोले

2017 से पहले था रूल ऑफ माफिया, हमने लागू किया 'रूल ऑफ लॉ'

लखनऊ (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश शुरू ऑफ माफिया से मुक्त हुआ है और शुरू ऑफ लॉ लागू हुआ है। वर्ष 2017 से पहले कानून-व्यवस्था और निवेश को लेकर संदेह रहता था। माफिया से विकास बाधित था। सरकार ने कानून का शासन स्थापित कर प्रदेश की छवि बदली है। कोई व्यक्ति या पद संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से कहा कि अन्याय सामने हो तो चुप रहना विकल्प नहीं है। फैंसला इतिहास सुनाएगा, लेकिन बहस आपको करनी है।

मुख्यमंत्री योगी शनिवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने भेषावियों को पदक

दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के साथ 25 जून 1975 भी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण तारीख है। आपातकाल ने 'रूल ऑफ लॉ' और 'रूलर ऑफ लॉ' का अंतर समझाया। न्यायमूर्ति एचआर खन्ना की असहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि सिद्धांतों के पक्ष में लिया निर्णय इतिहास में स्थान बनाता है। युवा अधिवक्ताओं को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र वद, धर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः को चौबर की दीवार पर नहीं, हृदय में उतारें। सत्य और निरंतर अध्ययन अधिवक्ता के जीवन का आधार हो। डॉ. लोहिया के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि विधिवेत्ता में शिव जैसा मस्तिष्क, कृष्ण जैसा हृदय और राम जैसा वचन होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत की परिकल्पना को मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया। कहा कि

140 करोड़ देशवासियों के इस दावे की पैरवी तथ्यों, साक्ष्यों और ईमानदारी से करनी होगी। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका होगी। प्रदेश को 2029-30 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कार्ययोजना तैयार है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम आसान कर सकती है, लेकिन अंतिम

निर्णय इंसान के विवेक से होना चाहिए। लापरवाह मसौदे से निर्दोष व्यक्ति को स्वतंत्रता गंवानी पड़ सकती है। डीपफेक और साइबर अपराधों ने साक्ष्यों की विश्वसनीयता की चुनौती पैदा की है। प्रदेश के 75 जिलों में साइबर थाने और 1,583 थानों में साइबर हेल्प डेस्क हैं। शएआई प्रज्ञा से 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने, जड़ों से जुड़े रहने और निरंतर अध्ययन की सीख दी। कहा कि गांवों में जमीन और पारिवारिक विवादों के समाधान में योगदान दें। गलत काम का दबाव आए तो सिद्धांतों से समझौता न करें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि उपाधि मंजिल नहीं, नई यात्रा की शुरुआत है।

मोदी व शाह जानते हैं कि जिस दिन सत्ता हाथ से गई, उनकी मनमानी की कहानी खत्म : राहुल गांधी

नयी दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्राओं और महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा कथित तौर पर की गई बदसलूकी को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं कि सत्ता हाथ से जाते ही उनकी मनमानी

की कहानी खत्म हो जाएगी। गांधी ने कुछ लड़कियों के साथ बातचीत का एक वीडियो श्वक्सर पर साझा किया, जिसमें उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस पर उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया, यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और निजी अंगों पर हमला, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाली छात्राओं तथा महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता शर्मनाक हदें पार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि यह कथित कार्रवाई आवाज दबाने की कोशिश का हिस्सा है और इसका उद्देश्य विरोध करने वालों को इतना डराना एवं अपमानित करना है कि वे दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत न करें।

बच्चों के अश्लील कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

कमाई जब्त करने के निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी अश्लील सामग्री को रोकने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नाकामी पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने निर्देश दिया है कि ऐसी सामग्री को पेवॉल या पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए भी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने की व्यवस्था पर विचार करने और प्रतिबंधित सामग्री से होने वाली कमाई जब्त करने को लेकर भी निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि 2024 में निर्देश दिए जाने के बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनका ठीक से पालन नहीं किया। 15 अक्तूबर को दिए गए आदेश में पीठ ने कहा कि दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी इस

दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। शीर्ष अदालत ने बच्चों की सुरक्षा और उनके कल्याण को लेकर सामने आई हालिया खबरों पर भी गहरी चिंता जताई।

शीर्ष अदालत के फैंसले के मुताबिक, किसी भी इंटरनेट मध्यस्थ को बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री या बच्चों को

नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी सामग्री को पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए उपलब्ध कराने, अपलोड करने, प्रचारित करने या साझा करने की अनुमति नहीं होगी।

प्रतिबंधित सामग्री से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कमाई करने वाले प्लेटफॉर्म की उस सामग्री से हुई कमाई जब्त कर वापस

लेने की व्यवस्था करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और उसके नियमों के तहत प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियों का उल्लंघन करने पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने की व्यवस्था पर विचार करने को कहा है।

बच्चों के अश्लील कंटेंट पर सुप्रीम प्रहार!

लेने की व्यवस्था करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और उसके नियमों के तहत प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियों का उल्लंघन करने पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाने की व्यवस्था पर विचार करने को कहा है।

कानूनी पेशा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं

लॉ के छात्रों से सीजेआई सूर्यकांत बोले- समाज के लिए भी काम करें

बंगलूरु (एजेंसी)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों से न्याय कायम रखने, स्वतंत्रता की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे में साहस, ईमानदारी और उन लोगों की बात सुनने की क्षमता जरूरी है, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है।

सीजेआई बंगलूरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) के 44वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, शकानूनी शिक्षा केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसका उद्देश्य छात्रों को अलग-अलग विचारों और नजरियों को समझने तथा समाज की सेवा करने के लिए तैयार करना भी है।

सूर्यकांत ने छात्रों से कहा, मैं आपको केवल बधाई ही नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपसे मुझे बहुत उम्मीदें भी हैं। उन्होंने

कहा, कानूनी शिक्षा का उद्देश्य आपराधिक या संवैधानिक कानून के सिद्धांतों को सीखने तक सीमित नहीं है। इसका असली महत्व उन लोगों से मिलने और उनके नजरिये को समझने के अनुभव में है, जो दुनिया को हमसे अलग तरह से देखते हैं।

कानूनी पेशे की जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसके लिए कानूनों और अदालती फैसलों की जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है। न्याय के पक्ष में खड़े होने का साहस और उन लोगों की चिंताओं को समझने की विनम्रता भी जरूरी है, जिनकी बातों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता।

उन्होंने कहा, कानूनी पेशा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसमें कानूनों और अदालती फैसलों की जानकारी के साथ न्याय की रक्षा करने का साहस और उन आवाजों को सुनने की विनम्रता भी चाहिए, जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है।

सीजेआई ने कानून के नए स्नातकों को आगाह किया कि वे सुविधा के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता न करें और पेशेवर जीवन में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने छात्रों से संस्थान में सीखे गए मूल्यों को अपने कामकाज का मार्गदर्शक बनाने की अपील की।

संविधान की रक्षा करें, मूल्यों से समझौता न करें

युवा वकीलों को सीएम डीके शिवकुमार ने क्या सलाह दी?

कोलकाता (एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने युवा वकीलों से कहा है कि वे सवाल पूछना कभी बंद न करें, अपने मूल्यों से समझौता न करें और आम लोगों को कभी न भूलें। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र वह नहीं है, जहां हर व्यक्ति सरकार की बात से सहमत हो, बल्कि वह है जहां नागरिकों को सरकार से सवाल

पूछने की आजादी मिले। शिवकुमार ने ये बातें शनिवार को बंगलूरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) के 44वें दीक्षांत समारोह में कहीं। समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरु और अन्य न्यायाधीश मौजूद थे। शिवकुमार ने कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों से लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और न्याय व्यवस्था की रक्षा करने की अपील की।

दैनिक एवं साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र

Website

www.shaharsamta.com

Subscribe on YouTube

youtube.com/@shaharsamtanews

सही खबर, सही समय पर

PRESS
हमेशा आपके साथ

शहर समता
संयम ★ संस्कार ★ संतुलन

स्थापित 2001 • RNI Dainik UPHIN/2004/22466 • साप्ताहिक UPHIN/2001/03996 • कार्यालय 289/238 A कर्मलगंज प्रयागराज • संपर्क 9005239332, 9450482227

मृत डिक्रीधारक का नाम रहने से निष्पादन कार्यवाही शून्य नहीं होगी, याचिका खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संयुक्त डिक्रीधारकों में से किसी एक की मृत्यु निष्पादन अर्जी दाखिल होने से पहले हो जाती है तो इससे पूरी कार्यवाही स्वतः शून्य नहीं हो जाती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संयुक्त डिक्रीधारकों में से किसी एक की मृत्यु निष्पादन अर्जी दाखिल होने से पहले हो जाती है तो इससे पूरी कार्यवाही स्वतः शून्य नहीं हो जाती। यदि जीवित संयुक्त डिक्रीधारक को पूरी डिक्री के निष्पादन का कानूनी अधिकार है तो मृत डिक्रीधारक का नाम हटाना या पक्षकारों का विवरण दुरुस्त करना प्रक्रियात्मक सुधार माना जा सकता है।

न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने यह टिप्पणी करते हुए निष्पादन कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मामला वर्ष 2003 में दाखिल बेदखली के मुकदमे से जुड़ा है। गाजियाबाद निवासी विनोद कुमार और अनिल कुमार के पक्ष में पांच जुलाई 2014 को डिक्री पारित की गई थी। पुनरीक्षण याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान विनोद कुमार की मौत हो गई। 20 अक्तूबर 2023 को निष्पादन वाद दाखिल किया गया। इसमें दोनों मूल डिक्रीधारकों के नाम दर्ज थे। हाईकोर्ट ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 15 का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवित संयुक्त डिक्रीधारक पूरी डिक्री के निष्पादन की मांग कर सकता है। संपत्ति के कथित हस्तांतरण की वैधता और प्रभाव का निर्धारण निष्पादन अदालत करेगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि निष्पादन की कार्यवाही कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जाए।

एक ही साक्ष्य को एक आरोप में अविश्वसनीय मानना तो दूसरे में स्वीकार करना उचित नहीं है

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल पुराने आपराधिक मामले में बांदा निवासी बलराम को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की एकल पीठ ने कहा कि एक ही साक्ष्य को एक आरोप में अविश्वसनीय मानना तो दूसरे में स्वीकार करना उचित नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल पुराने आपराधिक मामले में बांदा निवासी बलराम को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की एकल पीठ ने कहा कि एक ही साक्ष्य को एक आरोप में अविश्वसनीय मानना तो दूसरे में स्वीकार करना उचित नहीं है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत के फैसले को अवैध और विरोधाभासी मानते हुए रद्द कर दिया। बांदा के सहायक सत्र न्यायाधीश ने 20 जून 1984 को बलराम को दुष्कर्म के आरोप में चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, इसी मामले में उसे अपहरण और युवती को भगाने के आरोपों से बरी कर दिया गया था। अभियोजन के अनुसार 22 जुलाई 1983 को युवती बाजार गई थी। इसके बाद वह लापता हो गई। वहीं, दो महीने बाद 23 सितंबर 1983 को मिली। यात्री ने ट्रायल कोर्ट की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और सजा का आदेश निरस्त कर दिया।

18 नहीं 20 साल में बन सकेंगे स्टेशन मास्टर, रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाई

प्रयागराज। रेलवे ने स्टेशन मास्टर पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी है, हालांकि अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष पर यथावत रखी गई है। रेलवे ने स्टेशन मास्टर पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी है, हालांकि अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष पर यथावत रखी गई है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली के प्रावधानों में संशोधन कर नया बदलाव लागू किया गया है जो पत्र जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे, उत्पादन इकाइयों और रेलवे भर्ती बोर्डों (आरआरबी) के अध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश भेजते हुए अग्रिम सुधार आदेश जारी कर दिया है। रेलवे प्रशासन स्पष्ट किया है कि जिन भर्तियों के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं, उनकी चयन प्रक्रिया पुराने नियमों के अनुसार ही पूरी की जाएगी।

राम वन गमन का मंचन देख भावुक हुए लोग

प्रयागराज। शुक्रवार को नैनी में विभिन्न रामलीला समितियों द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। इसमें राम वन गमन, शबरी आश्रम, राम–सुग्रीव मित्रता, बालि वध और राम–सीता विवाह का मंचन किया गया। दर्शकों ने भावुक होकर इन दृश्यों का आनंद लिया। मानस रामलीला समिति ने राम वन गमन लीला का मंचन किया। रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से राम के लिए चौदह वर्ष का वनवास मांगा। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान करते हैं। पीडीए कॉलोनी की श्री अवंतिका रामलीला में शबरी आश्रम का दृश्य दिखाया गया। भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। शबरी को नवधा भक्ति की शिक्षा देने के बाद उन्होंने देह त्याग दी। श्री रामलीला कमेटी चीनी मिल ने परशुराम–लक्ष्मण संवाद का मंचन किया। इसके बाद राजा दशरथ जनकपुर बरात लेकर पहुंचे। विद्वान आचार्यों ने सीता–राम का विवाह संपन्न कराया। सार्वजनिक रामलीला समिति ट्रस्ट ने स्वर्ण मृग, लक्ष्मण रेखा और सीता हरण का मंचन किया। रावण ने छद्म वेश में आकर माता सीता का हरण किया। इसके बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले। उन्होंने शबरी के आश्रम पहुंचकर उनसे भेंट की। हनुमान से मिलन के बाद राम ने सुग्रीव से मित्रता की। उन्होंने अहंकारी बालि का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया।

सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत

प्रयागराज। उत्तरांव के कसियाकापुर गांव निवासी विशाल गुप्ता (25) की शुक्रवार दोपहर सड़क हादसे में मौत हो गई। वह बबुरिहा हाईवे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया था। विशाल सुबह किसी काम से घर से निकला था और दोपहर में लौट रहा था। टक्कर से उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर उत्तरांव पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। मृतक विशाल तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और फुलकी बेचने का काम करता था।

लाल महेंद्र चौधरी बने यमुनापार जिलाध्यक्ष

प्रयागराज। आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर संतानात्मक मजबूती को लेकर नए नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। इसके तहत प्रयागराज (यमुनापार) के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी लालापुर के छतहरा धुरेहटा निवासी लाल महेंद्र चौधरी को सौंपी गई है। इसी के साथ बलिया में अंश राव बीरू और फिरोजाबाद में प्रवीण उमराय बाल्मीकि को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

महाकुंभ के दौरान लगी 76 फीसदी लाइट खराब, फर्म ब्लैक लिस्ट कर 70 लाख जब््त, नगर निगम ने की कार्रवाई

नगर निगम के कार्यालय में लाइट खराब होने पर नाराज लोग

प्रयागराज। महाकुंभ–2025 के दौरान प्रयागराज में लगाई गई सजावटी लाइटों के रखरखाव में बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर निगम के निरीक्षण में 76.15 फीसदी मोटिफ लाइटें खराब मिलीं,



जबकि 301 मोटिफ गायब पाए गए। कार्रवाई करते हुए निगम ने संबंधित फर्म को तीन साल के लिए काली सूची में डाल दिया है। साथ ही पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ करीब 70 लाख रुपये की जमानत और रखरखाव धनराशि भी जब््त कर ली है।

महाकुंभ–2025 के दौरान लगी लाइट के मामले में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। नगर निगम ने खराब लाइट का रखरखाव नहीं करने पर मेसर्स द क्लाइमेट मेकर्स (सेल्स) फर्म को काली सूची में डाल दिया है। फर्म पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसके साथ ही निगम ने फर्म की करीब 70 लाख रुपये की जमानत और रखरखाव धनराशि भी जब््त कर ली है। महाकुंभ के दौरान लगी 76 फीसदी लाइट खराब हो गई हैं।

यह कार्रवाई महाकुंभ

मेला–2025 के थिमैटिक लाइटिंग कार्यों में लापरवाही की वजह से की गई है। निगम ने फर्म को कई बार नोटिस जारी किए थे। इनमें फर्म से दो सप्ताह में खराब स्पाइरल लाइटों और मोटिफ्स को ठीक करने

नगर निगम के कार्यालय में लाइट खराब होने पर नाराज लोग

को पूरा हुआ और कार्य एक सितंबर 2024 से शुरू हुआ। नगर निगम सीमा में 2842 स्पाइरल लाइट, 2080 मोटिफ्स और 2842 लाल रंग की स्ट्रिप की आपूर्ति की गई थी। इनकी स्थापना 20 जनवरी 2025 को

पूरी हुई। निविदा शर्तों के अनुसार, मोटिफ्स लाइट के लिए एक वर्ष और स्पाइरल लाइटों के लिए तीन माह की दोष देयता अवधि निर्धारित थी। इन कार्यों का संचालन और रखरखाव भी फर्म को करना था लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया। मुख्य अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) संजय कटियार ने फर्म पर रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगाया है।

चोरी के दावे और निगम की असंतुष्टि मुख्य अभियंता कार्यालय ने 13 मई 2025 को फर्म को पहला नोटिस भेजा था। इसमें सभी बंद स्पाइरल और मोटिफ्स लाइट को तुरंत जलाने का निर्देश था। फर्म ने इस पर कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद 29 अगस्त 2025 को एक और आदेश जारी किया गया। फर्म ने छह सितंबर 2025 को

सतीश श्रीवास्तव हत्याकांड: आरोपी पिता-पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बोले- मारपीट के बाद मारी थी गोली

सतीश श्रीवास्तव की पत्नी

प्रयागराज। सलोरी में जमीन के विवाद में ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के लैब अटेंडेंट व अधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता–पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। सलोरी में जमीन के विवाद में ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के लैब अटेंडेंट व अधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता–पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में देवेंद्रनाथ मिश्रा ने बताया कि सतीश से नजूल की संपत्ति पर कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

बृहस्पतिवार को वह अपने बेटे नृपेंद्रनाथ मिश्रा और अन्य लोगों के साथ जमीन पर कब्जे की नीयत से बाउंड्री फांदकर अंदर गया और वहां सतीश के साथ मारपीट करने के बाद उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी।

कर्नलगंज पुलिस ने शुक्रवार को देवेंद्रनाथ मिश्रा उर्फ झुन्ने और उसके बेटे नृपेंद्रनाथ मिश्रा को बेली अस्पताल के मुख्य गेट से पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक खोखा कारतूस और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बरामदगी के आधार पर प्राथमिकी में ऑर्म्स एक्ट की बढोतररी की गई है। वहीं, पुलिस ने आरोपियों को जिला न्यायालय के समक्ष पेश

करने के बाद जेल भेज दिया है।

हत्या से एक दिन पहले मारपीट का वीडियो वायरल सतीश की हत्या से एक दिन पहले का करीब डेढ़ मिनट का वीडियो भी सामने आया है। इसमें जमीन के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती दिख रही है। वीडियो में सतीश की पत्नी वर्षा श्रीवास्तव, दूसरे



पक्ष के देवेंद्रनाथ मिश्रा और कुछ अन्य लोग नजर आ रहे हैं। मौके पर ईश्वर शरण चौकी प्रभारी विनय यादव और उनका हमराही भी दिखाई दे रहे हैं। सतीश की पत्नी पहले ही आरोप लगा चुकी हैं कि उनके पति को पुलिस की मौजूदगी में गोली मारी गई थी। वीडियो सामने आने पर पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

फरार आरोपियों की तलाश में दबिश, मोबाइल फोन बंद

सतीश श्रीवास्तव की पत्नी

भाजपा छोड़कर विदुप अग्रहरि सपा में शामिल, अखिलेश की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता

प्रयागराज। प्रयागराज के उद्यमी और वैश्य बिरादरी के बड़े चेहरों में गिने जाने वाले विदुप अग्रहरि ने शुक्रवार को भाजपा का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रयागराज के उद्यमी और वैश्य बिरादरी के बड़े चेहरों में गिने जाने वाले विदुप अग्रहरि ने शुक्रवार को भाजपा का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लखनऊ स्थित पार्टी के राज्य कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव की मौजूदगी में उन्होंने औपचारिक रूप से सपा की सदस्यता ग्रहण की। विदुप का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब वह भाजपा में काफी समय से सक्रिय थे और पार्टी के क्षेत्रीय सह संयोजक व्यावसायिक प्रकोष्ठ जैसी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनका सपा में शामिल होना राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा का विषय बन गया है। इसके साथ ही उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। सपा में शामिल होने के बाद विदुप ने सपा प्रमुख की सादगी और कार्यशैली को अपनी इस सियासी पसंद की बड़ी वजह बताया। खास बात यह है कि विदुप अग्रहरि की राजनीतिक विरासत काफी मजबूत रही है।

जवाब दिया कि असामाजिक तत्वों की तरफ से एलईडी मोटिफ्स के अडॉप्टर और स्पाइरल लाइट के तार चुरा लिए गए हैं। हालांकि सितंबर 2025 में हुए सर्वेक्षण में चोरी का कोई मामला नहीं पाया गया। मुख्य अभियंता कार्यालय ने फर्म के इस स्पष्टीकरण पर पूरी तरह से संतुष्टि नहीं जताई है। वित्तीय कार्रवाई और अनुबंध का उल्लंघन

नगर निगम ने फर्म की 47,87,611 रुपये की जमानत धनराशि जब्त कर ली है। इसके अतिरिक्त, रखरखाव कार्य के सापेक्ष 22,73,500 रुपये भी जब््त किए गए हैं। कुल मिलाकर करीब 70 लाख रुपये की धनराशि जब्त की गई है। फर्म को इस वर्ष 21 अप्रैल, 11 सितंबर और 14 सितंबर को भी नोटिस भेजे गए थे।

दिसंबर 2025 में पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। फर्म ने 19 सितंबर को अत्यधिक वर्षा को खराबी का कारण बताया और मरम्मत के लिए 15 से 20 दिन मांगे थे। इसके जवाब में 22 सितंबर को दो सप्ताह में लाइट ठीक करने का अंतिम नोटिस दिया गया लेकिन फर्म ने कोई कार्रवाई नहीं की।

महाकुंभ के दौरान लगाई गई लाइट के रखरखाव में लापरवाही देखने को मिली है। इनमें 76 फीसदी लाइट खराब हो गई हैं। इसके बाद फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के साथ पांच लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा रखरखाव के 70 लाख रुपये भी जब्त कर लिए गए हैं। – साईं तेजा, नगर आयुक्त

लेकर भी चर्चा हो रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने सलोरी स्थित विवादित जमीन की नए सिरे से जांच कराने की बात कही है।

सतीश श्रीवास्तव हत्याकांड में नामजद आरोपी देवेंद्रनाथ मिश्रा और उसके बेटे नृपेंद्रनाथ मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक खोखा और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों से पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। – सागर जैन, डीसीपी नगर

सतीश कुमार श्रीवास्तव के शव का शुक्रवार देर शाम अंतिम संस्कार कराया गया। दोपहर करीब तीन बजे पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर सलोरी स्थित घर पहुंचे, लेकिन मुआवजे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। सतीश की पत्नी वर्षा श्रीवास्तव और परिवार के अन्य सदस्य अपनी मांगों पर अड़े रहे। करीब तीन घंटे तक चले हंगामे के दौरान परिजनों ने एक करोड़ रुपये मुआवजा, दोनों बेटियों को सरकारी नौकरी, परिवार को आजीवन सुरक्षा देने और आरोपी का घर गिराने की मांग की। सूचना पर परिजनों को समझाने और अंतिम संस्कार कराने के लिए एसीपी कर्नलगंज विवेक यादव, एसीपी झूंसी अरुण पाराशर, एसडीएम अंकित वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिवार से बातचीत कर उन्हें मनाने का प्रयास किया। काफी देर तक चली बातचीत के बाद पांच लाख मुआवजा, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन, शस्त्र लाइसेंस, सुरक्षा उपलब्ध कराने समेत अन्य मांगों का आश्वासन दिया गया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए और देर शाम रसूलाबाद घाट पर छोटी बेटी वैशाली ने पिता के शव का अंतिम संस्कार किया।

संपर्क मार्ग अधूरा होने से आवागमन मुश्किल

प्रयागराज। बहरिया क्षेत्र का कहली–गमरहटा संपर्क मार्ग करीब बीस साल से अधूरा है। इससे पांच गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ठेकेदार गिट्टी और मौरंग डालकर चला गया, निर्माण पूरा नहीं किया। सड़क पर बिखरी गिट्टी और मौरंग से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। हाल ही में रमेश कुमार भारतीय बाइक से जाते समय गिट्टी पर फिसलकर घायल हो गए। ग्रामीण रामकुमार मौर्य के अनुसार, मार्ग की हालत वर्षों से खराब है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क मार्ग का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है।

करनाईपुर में जर्जर पंचायत भवन, हादसे का खतरा

प्रयागराज। बहरिया क्षेत्र के गमरहटा गांव में करीब 25 वर्ष पुराना पंचायत भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इसकी कमजोर दीवारों और छत से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भवन आसपास बच्चों के खेलने और ग्रामीणों की आवाजाही से खतरा बढ़ गया है। नया सचिवालय बनने के बावजूद पुराने भवन का ध्वस्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। भवन का ढांचा इतना कमजोर है कि कोई भी हिस्सा कभी भी ढह सकता है, जिससे जानमाल का नुकसान संभव है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भवन की तत्काल जांच कराने और नियमानुसार ध्वस्तीकरण की मांग की है। उन्होंने सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने पर भी जोर दिया। ग्राम प्रधान सुखराज ने भी अधिकारियों से इस जर्जर भवन को जल्द ध्वस्त कराने की अपील की है।

जल निकासी के खिलाफ किसानों का तीसरे दिन भी धरना जारी

प्रयागराज। कौड़िहार में जल निकासी की समस्या को लेकर शुक्रवार को तीसरे दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। किसानों ने अधिकारियों की कथनी और करनी पर नाराजगी जताई। युवा विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने धरने का नेतृत्व किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तीन दिनों से किसान धरने पर हैं, पर अधिकारी उनकी बातें नहीं सुन रहे। दोपहर में नहर विभाग के अधिशासी अभियंता एके सिंह ने मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने पक्के नाले से मलबा हटाने का निर्देश दिया। किसानों का कहना है कि अधिकारी उनकी समस्याएं सुने बिना ही चले गए। उन्हें गुमराह किया जा रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। करीब आधा दर्जन गांवों की धान फसल बर्बाद हो गई है। अब मवेशियों के चारे का भी संकट उत्पन्न हो गया है। किसानों ने समस्या के समाधान तक धरना जारी रखने की बात कही। मौके पर सांलिक राम पटेल, मोनू सिंह, दरोगा यादव, दिवंकल सिंह, नूरमोहम्मद आदि रहे।

ट्रेन से गिरकर घायल युवक की गई जान

प्रयागराज। दिल्ली–हावड़ा रूट पर मेजा के अमिलिया कला गांव के सामने बृहस्पतिवार रात एक युवक ट्रेन से गिरकर घायल हो गया। शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। मांडा थाना क्षेत्र के लखन चौकठा गांव के अनूप मिश्र (24) प्रतिदिन प्रयागराज से मेमो ट्रेन से लौट रहे थे। बताया जाता है कि वह ट्रेन के गेट पर खड़े थे। अमिलिया कला के सामने वह ट्रेन से नीचे गिर गए। गंभीर रूप से घायल अनूप को परिजन उपचार के लिए शहर ले जा रहे थे। रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इकलौते बेटे की मौत से माता–पिता का बुरा हाल है। मेजा थाने के इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने घटना को लेकर अनभिज्ञता जताई है।

जस्टिस सत्यवीर सिंह: जिस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रातें गुजार कर संवारते थे भविष्य, उसी में होगा अभिनंदन

प्रयागराज। किसान परिवार में जन्म, माता–पिता के संस्कार और शिक्षा के प्रति अटूट समर्पण। इन्हीं आधारों पर अलीगढ़ के छोटे से गांव नहल से इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ तक का सफर तय करने वाले न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की कहानी प्रेरणा देती है। जिस मौलाना आजाद लाइब्रेरी में उन्होंने रात–रात भर पढ़ाई कर अपने सपनों को आकार दिया, उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सर सैयद डे के अवसर पर वह अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। यह अवसर उनके लिए सम्मान के साथ अपनी शैक्षणिक यात्रा से दोबारा जुड़ने का भी है।

कुछ सपने सुविधाओं के सहारे नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन और शिक्षा के प्रति समर्पण से पूरे होते हैं। न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की जीवन यात्रा इसकी मिसाल है। अलीगढ़ की अतरौली तहसील के छोटे से गांव नहल में किसान परिवार में जन्मे सत्यवीर सिंह ने अपनी लगन और परिश्रम से इलाहाबाद हाईकोर्ट की गरिमामयी पीठ तक का सफर तय किया। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एमयू) में सर सैयद डे के अवसर पर अतिथि के रूप में उनका स्वागत होगा। यह उनके लिए उस परिसर में लौटने जैसा है, जहां उनकी शैक्षणिक यात्रा के महत्वपूर्ण अध्याय लिखे गए।

जिस लाइब्रेरी में गढ़ा भविष्य, वहीं होगा अभिनंदन न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह के विद्यार्थी जीवन में एएमयू की मौलाना आजाद लाइब्रेरी की खास भूमिका रही है। परास्नातक की पढ़ाई के दौरान वह रात 9रू30 बजे से सुबह 5रू30 बजे तक लाइब्रेरी में अध्ययन करते थे। किताबों के बीच बिताए गए ये घंटे उनके जीवन की अमूल्य पूंजी बने। 24 घंटे खुलने वाली इस लाइब्रेरी ने उन्हें केवल पढ़ने की जगह ही नहीं दी, बल्कि समानता, सहयोग और आपसी अपनत्व का अनुभव भी कराया। वहां अमीर–गरीब, जाति और मजहब के भेद से ऊपर उठकर विद्यार्थी साथ पढ़ते और साथ भोजन करते थे। न्यायमूर्ति सिंह के लिए यह अनुभव आज भी विशेष महत्व रखता है। लाइब्रेरी में कभी उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने का एहसास नहीं हुआ। विद्यार्थियों के बीच पारिवारिक अपनत्व और समानता का भाव ऐसा था, जिसने उनके जीवन पर गहरी छाप छोड़ी।

किसान पिता के संस्कार बने जीवन की ताकत न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह का जन्म अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के नहल गांव में हुआ था। उनके पिता मोहन लाल किसान थे और मां पाना देवी गृहिणी थीं। पिता शिक्षा के महत्व को समझते थे और उन्होंने अपने पांचों बेटों को पढ़ाया–लिखाया। न्यायमूर्ति सिंह अपने पिता की ईमानदारी, मेहनत और धैर्य को जीवन की महत्वपूर्ण सीख मानते हैं। इन्हीं संस्कारों ने उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। उनकी यात्रा बताती है कि मजबूत पारिवारिक संस्कार और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं।

शिक्षा को सामाजिक बदलाव का माध्यम मानते हैं न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह शिक्षा को सामाजिक बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। उनका मानना है कि गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को भी बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलने

संक्षिप्त

गोमती नदी का जलस्तर घटने पर खुला

चंद्रिका देवी मंदिर

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी के बीकेटी में स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर शनिवार को भक्तों के लिए खोल दिया गया। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मंदिर जाने वाले रास्ते पानी में डूब गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर को बंद कर दिया गया था। शुक्रवार को मंदिर परिसर की साफ–सफाई की गई। इसके बाद शनिवार से भक्तों के लिए दर्शन शुरू हो गए। मंदिर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार शाम को डीसीपी नॉर्थ अमित कुमार आनंद ने मंदिर परिसर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था देखी थी।

एनसीसी कैडेट्स ने नागरिकों को सिखाए यातायात सुरक्षा के नियम

लखनऊ (संवाददाता)। खाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की एनसीसी इकाई ने मिशन शक्ति के तहत यातायात जागरूकता अभियान चलाया। 20 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी, लखनऊ के सहयोग से विश्वविद्यालय परिसर के बाहर आयोजित अभियान का नेतृत्व कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने किया। कुलपति ने कहा कि यातायात नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन का दायित्व नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अभियान के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने यातायात संचालन में सहयोग किया और आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने तथा सड़क पर अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। अभियान का संचालन एनसीसी की एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉ. बुशरा अलवेरा के मार्गदर्शन में किया गया।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि में छह दिसम्बर को कारसेवा को लेकर संगोष्ठी

लखनऊ (संवाददाता)। योगी सेना (भारत) के तत्वावधान में श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण को लेकर संगोष्ठी का आयोजन यहां चौहान पुरम, हनुमानपुरी, सरोजनी नगर आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेना प्रमुख गौरव वर्मा ने कहा की 134 करोड़ सनातनियों के आस्था के प्रतीक श्री कृष्ण भगवान हैं आस्था को देखते हुए योगी सेना (भारत) ने पूरे प्रदेश संगोष्ठी का आयोजन कर रही है जिससे आगामी छह दिसंबर को सेना हजारों हिन्दुओं के साथ कारसेवा करेगी। श्री वर्मा ने योगी सरकार से अपेक्षा करते हुये कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर मालिकाना हक दिलाते हुए भव्य श्री कृष्ण भगवान मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द करेगी। संगोष्ठी में मौजूद उपाध्यक्ष मोहित मिश्रा ने हिंदुओं की तीज त्यौहार दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जिसमे गरबा डांडिया महोत्सव हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़ा है इसकी पवित्रता से यदि किसी ने खिलवाव किया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी हमारे कार्यक्रम में मुसलमान लड़के तिलक और कलावा बांधकर लव जिहाद के उद्देश से कार्यक्रमों में प्रवेश करते हैं। संगोष्ठी में उपस्थित राष्ट्रीय सचिव सूरज साहू, प्रदेश मंत्री महेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन चौधरी, जिला सचिव उमेश साहू, युवा नेता कपिल वर्मा, विशाल तिवारी, ज्योति वर्मा, गीतांजलि, शांतनु ठाकुर, विनीत मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे।

पंचायत चुनाव : सुप्रीम कोर्टनही जायेगी सरकार

लखनऊ (संवाददाता)। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगमी जोरों पर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने का कड़ा आदेश आने के बाद अब सूबे की सरकार के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिक गई हैं।सूबे के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटायेगी। जैसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट हाथ लगेगी, तय समय सीमा के अंदर ही चुनाव कराने की मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक सरकार अदालत के हर निर्देश का पूरा सम्मान करती है। चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन पहले ही पूरा किया जा चुका है। कोर्ट के निर्देशानुसार अगर समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने वाले एक महीने के भीतर मिल जाती है, तो उसके ठीक अगले दो महीनों के अंदर चुनाव की पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है। जहां सरकार हाई कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन ने हाई कोर्ट के इस आदेश को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है। संगठन आने वाले सप्ताह में ही इस मामले को लेकर अपील दायर कर सकता है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी समयसीमा पर क्या रुख अपनाता है। सिर्फ ग्राम प्रधान ही नहीं, बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष संघ और ब्लॉक प्रमुख संघ ने भी जल्दबाजी में होने वाले चुनावों को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। उनका तर्क है कि सूबे के कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, ऐसे हालात में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। चुनाव की घोषणा होने से गांवों में इस समय चल रहे तमाम जरूरी विकास कार्यों के रुकने की भी पूरी आशंका जताई जा रही है।

बैंक मजबूत हुए हैं तो खाते से क्यों काटे जा रहे हैं पैसे ? अखिलेश यादव के 12 साला

लखनऊ (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बैंकिंग व्यवस्था को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर 12 सवाल किया है। अखिलेश ने बारह साल, बारह सवाल के जरिए बैंकों की मजबूती, खातों से कटने वाले पैसे, लोन की उपलब्धता, साइबर ठगी और बैंक कर्मचारियों की भर्ती जैसे मुद्दे उठाए। अखिलेश ने सवाल किया कि अगर बैंक मजबूत हुए हैं तो आम जनता को इन परेशानियों से राहत क्यों नहीं मिल रही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उनका पहला सवाल था, बैंक मजबूत हुए हैं तो फिर बेचे क्यों जा रहे हैं? दूसरा सवाल, बैंक मजबूत हुए हैं तो गरीब जनता के खाते से पैसे क्यों काटे जा रहे हैं? तीसरा सवाल, बैंक मजबूत हुए हैं तो बार–बार केवाईडी के नाम पर जनता के पैसे देने से इन्कार क्यों किया जा रहा है? चौथा सवाल, उन लोगों को पकड़कर देश में लाकर सजा क्यों नहीं दी जा रही है, जो बैंकों से खरबों का लोन लेकर भाग गये हैं?

मिशन शक्ति अभियान के तहत बलदेव पुलिस ने महिलाओं और छात्राओं को किया जागरूक

महिला हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के बारे में बताया

बलदेव (मथुरा), 17 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान मिशन शक्ति फेज–6.0 के द्वितीय चरण के तहत थाना बलदेव की मिशन शक्ति पुलिस टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, यातायात नियमों तथा सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशान में आयोजित जागरूकता अभियान के दौरान छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को बताया कि बसों, रास्तों और सार्वजनिक स्थानों पर मनचलों या शोहदों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने पर डरने या चुप रहने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। इसके लिए वूमैन पावर लाइन 1090 और आपातकालीन पुलिस सेवा 112 का उपयोग करें। साथ ही, संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए भी जागरूक किया गया। सोशल मीडिया का सावधानी से करें इस्तेमाल अभियान के दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम

और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। पुलिस टीम ने साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताते हुए संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने, अपनी निजी जानकारी अनजान लोगों के साथ साझा



न करने और साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की जानकारी दी। इसके अलावा महिलाओं और बालिकाओं को यातायात नियमों का पालन करने तथा अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को सरकार की विभिन्न हेल्पलाइन

सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। इनमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, वूमैन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108,

और जरूरतमंद विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।

योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (ऌ्के), उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (ऌ्के), नीट

(छम्प्), जेईई (श्रम्), एनडीए (छक्) और सीडीएस (ब्लै) सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण तथा विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। पुलिस टीम ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आर्थिक संसाधनों की कमी को अपनी सफलता में बाधा न बनने दें और उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने भविष्य को बेहतर बनाएं।

भक्ति और शक्ति का आराधना पर्व है महानवमी: अशोक

आहलादित कर उठता है। हमारे वेदों पुराणों और पौराणिक आख्यानों के अनुरूप धरती पर अत्याचार और क्रूरता के पर्याय महिषासुर जैसे राक्षसों का मां



दुर्गा द्वारा वध किए जाने का यह आलोक और इसके ठीक बाद असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा महापर्व हमारे समाज में मानवीय मूल्यों का जागरण करता है।

इसके साथ ही साथ जप, तप, योग ध्यान, पूजा व्रत, उपासना सिद्धि, सदाचार,

स्वरूप हमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में साधना के भिन्न–भिन्न लोक मान्यताओं से अनुरंजित करता चला आ रहा है। गांव गली, हाट बाजार, शहर नगर चारों ओर यह भक्तिमय वातावरण दूसरी ओर हमारे समाज के एक प्रमुख स्तंभ आचार्य वेदपाठियों के लिए भी उनके भौतिक जीवन से जुड़ उठता है।

वहीं फल, फूल, पूजा सामग्री समेत विविध प्रकार के प्रयोग वस्तुओं के विक्रेता भी अपने आय को मजबूत बनाते हैं। दूसरी ओर पूजा के बहाने सही पूजा पाण्डालों में पास पड़ोस से एकत्र हुए लोगों के बीच यह महापर्व, भक्ति भावना आपसी समरसता और प्रेम का भी संचार कर उठता है। लोक–संगल, हमारी लोक परंपरा,लोकरीति और सनातन संस्कृति के लोकदर्शन का पर्याय बनकर व्रत, पूजन का यह लोक उत्सव अपने विविध पक्षों के साथ अनवरत गतिमान है।

फेक सर्वे पर भड़कीं मायावती, कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा संदेश

लखनऊ (संवाददाता)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कथित फेक सर्वेक्षणों के प्रचार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिवादी मीडिया और सोशल मीडिया धनबल का दुरुपयोग कर पंड्यंत्र के तहत बसपा को कमजोर दिखाने और जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं और बहुजन समाज के लोगों से ऐसे प्रचार से सतर्क रहने तथा उत्तर प्रदेश में पांचवीं बार बसपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटने की अपील की। मायावती ने शनिवार को कहा कि तीनों राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बसपा अच्छे और दमदार उम्मीदवारों के चयन सहित जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुटी है। इसी बीच कथित तौर पर फेक और ध्यान भटकाने वाले सर्वेक्षणों का प्रचार शुरू कर दिया गया है। उन्होंने इसे बसपा को निशाना बनाने की कोशिश बताते हुए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जातिवादी मीडिया की ओर से पार्टी के खिलाफ मिथ्या और अनर्गल प्रचार किया जाता रहा है। उनके मुताबिक, फेक और प्रायोजित सर्वेक्षणों में बसपा की ताकत को कम करके आंका जाता है, जिससे जनता के बीच भ्रम पैदा हो। मायावती ने वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी मीडिया का रवैया जातिवादी और द्वेषपूर्ण था। इसके बावजूद बसपा ने तमाम कयासों और उम्मीदों को गलत साबित करते हुए उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने और सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की भावना के अनुरूप संवैधानिक कल्याणकारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। बसपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी और अब भाजपा के शासन से त्रस्त सर्व समाज, खासकर बहुजन समाज के लोगों को विरोधी दलों और जातिवादी तत्वों के हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधी साम, दाम, दंड और भेद जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

नशामुक्ति जागरूकता बाइक रैली को डीजीपी ने दिखाई हरी झंडी

लखनऊ (संवाददाता)। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृति में राष्ट्रीय एकता दिवस 2026 मनाया जा रहा है। इसी को लेकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय से फाइट अगेन्स्ट ड्रग्स

मोटरसाइकिल रैली को पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पलेंग ऑफ कर रवाना किया। यह रैली समाज में नशे के विरुद्ध जन–जागरूकता बढ़ाने तथा नशामुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प को सशक्त करने के

उद्देश्य से निकाली जा रही है। पुलिस महानिदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल के सशक्त एवं अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए युवा पीढ़ी का नशामुक्त होना

आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित यह अभियान देश की सामूहिक इच्छाशक्ति का प्रतीक है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्यारा फूल गुलाब

सुगम मनोहर दिव्य है, प्यारा फूल गुलाब।
कोमल जिसकी पंखुरी, जिन्दा करते खूबाब।
जिन्दा करते खूबाब,रहे जो दिल में सोते।
कर खुशबू संचार, प्रेम रस उन्हें पिलाते।
सुन लो कहें प्रदीप, शब्द की गरिमा रखकर।
कहता पुष्प गुलाब, वक्त कर सुगम मनोहर।।

खूबाबों के संसार को, दिखा रहा जो दीप।
पावन पुष्प गुलाब है, रखिये उसे समीप।
रखिये उसे समीप, मिलेगा सुखमय जीवन।
भौतिकता से दूर, दिखेगा पावन मधुबन।
सुन लो कहें प्रदीप,अर्थ समझो शब्दों के।
जिसमें निहित यथार्थ,गमक बनते खूबाबों के।।

डॉ. प्रदीप चित्रांशी
लूकरगंज, प्रयागराज

अग्रसेन जयंती महोत्सव 20 अक्टूबर को होगा आयोजित

मथुरा। अग्रवाल समाज समिति (रजि.) बलदेव के तत्वावधान में अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन 20 अक्टूबर को शाम सात बजे होटल गोयल विरासत में किया जाएगा। अग्रवाल समाज समिति अध्यक्ष रोहित मोदी ने बताया कि महोत्सव में वृद्धजन सम्मान, वृद्ध माता सम्मान, रंगमंचीय कार्यक्रम तथा मेधावी छात्र–छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन सहभोज एवं लकी ड्रां के साथ होगा। वही जयंती महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सहभागिता करने की अपील की गई है।

68,500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का घर

लखनऊ (संवाददाता)। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के लखनऊ स्थित आवास का घेराव किया। दस्तक दो अभियान के तहत बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह और आशुतोष वर्मा ने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (उत्तर प्रदेश) ने अपनी रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट देने की सिफारिश की है। इसके तहत 150 नंबर के पूर्णांक में पासिंग मार्कंस 60 अंक (यानी 40:) करके नया संशोधित रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस सिफारिश के लागू होने से न केवल ओबीसी, बल्कि दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। अभर्थी तूफान सिंह के मुताबिक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया।

तुष्टीकरण के सहारे अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही सपा कांग्रेस : ब्रजेश पाठक

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के ज्यादातर हिस्सों में कांग्रेस पार्टी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के बल पर अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में उसका कोई जनाधार नहीं बचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राहुल गांधी को रायबरेली सीट को लेकर दी गई चुनौती का समर्थन करते हुए ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस सपा के बिना रायबरेली जीतने का सामर्थ्य रखती है?

 उत्तर मध्य रेलवे
 ई-निविदा सूचना
अरिष्ट मण्डल विद्युत अभियन्ता/परिचर/उपमहानिर्वाह/प्रमाणपत्र, ग्रुप भाग के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्न कार्य हेतु ई निविदा अन्वेषित की जाती है। विन्यास विवरण निम्न प्रकार है:-
निविदा सं० : 230-कटिगि-डायर टेंडर-1058-2026
कार्य का विवरण : प्रयामराज मंडल में वनपुर संकुल स्टेशन पर 12 कोय की मेसू रैक समायोजित करने हेतु पुरानी बॉक्सींग लाइनों के विस्तार के करण 25 kV ओवरहॉड से संशोधन और विद्युतीकरण का कार्य।
अनुमानित लागत : ₹ 2,16,48,501.05 किड सुरक्षा राशि : ₹ 4,33,000.00
कार्य अवधि : 12 महीना कोई प्रमाणी : एक पैंकेट
निविदा बन्द होने की तिथि तथा समय : 06.11.2026, 14:00 बजे
निविदा सुनने की तिथि तथा समय : 06.11.2026, 15:00 बजे
नोट:- 1. उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (निविदा प्रपत्र सहित) वेबसाइट www.irps.gov.in पर निविदा खोलने की तिथि से 21 दिन पहले से उपलब्ध होे। 2. उपरोक्त निविदा में ई बिज के अन्वया किसी अन्य रूप में किड लोडार नहीं की जायेगी। इन प्रपेडन हेतु केन्दों को खलिष्ट किं के अपने आन्वो डिस्टिन्ट हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ IREPS की वेबसाइट पर पंजीकृत करायें। 3. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के सम्बन्धन के लिए IREPS की वेबसाइट की हेल्प लाइन से सम्पर्क किया जा सकता है। 2389/26 (AS)
 North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in CPRONCR

उत्तर मध्य रेलवे

ई-प्रापण निविदा सूचना संख्या: 20/49

निम्नांकित निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमाण मुख्य सामग्री प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज (आई.एच.ओ. 9601-2815 प्रमाणित इकाई) निम्नलिखित भटों के लिए ई-प्रापण निविदायें आमंत्रित करते हैं।

क्र.सं.	निविदा संख्या	संक्षिप्त विवरण	ब्याग	निविदा सुनने की तिथि
1	6326RGC16	डिस्ट्रिक्ट टैंकर टू इंटर इन्ट्र रनिंग कान्ट्रैक्ट चरिर् मेन्सुक्चर रेंड सनाई ऑफ सीध्यास कोसिंग 52 केजी. 1 इन 12 इन्डिग नो टी. 4734 एंड सीध्यास कोसिंग 52 केजी. 1 इन 12 इन्डिग नो टी-4867	327.00 मी।	25.11.2026
2	30262021ए	ग्रुप भाग चरिर् सप्तमी कोयड	54 मी।	05.11.2026

नोट:- उपरोक्त सभी ई-प्रापण निविदाओं का पूरा विवरण IREPS वेबसाईट www.irps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदाओं में किसी भी ब्याग/सुटि-वग के लिए कृपया इस वेबसाईट को नियमित रूप से देखें। सम्बन्ध-वग में कोई अलग से सुटि/पत्र/परिचित प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

North central railways

CPRONCR

www.ncr.indianrailways.gov.in

2374/26 (A)

 उत्तर मध्य रेलवे
 ई-टेंडरिंग निविदा सूचना
निविदा सं० : 74-WTENDER/E/9020262027
निम्नांकित निविदा सूचना
भारत के राष्ट्रपति की ओर से बरि, मण्डल अभियन्ता/समन्वय/ उत्तर मध्य रेलवे/ प्रयामराज, निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (ई-टेंडरिंग) के माध्यम से खुली निविदा, आमंत्रित करते हैं।
ई निविदा सूचना सं० : 9026262027-188
कार्य का नाम: (A) सुवैद्यकीय IRTMT परियोजना में 25,000 बैटन क्षमता वाली एक RCC ओवरहैड टैंक का निर्माण। (B) उत्तर मध्य रेलवे के प्रयामराज मंडल के अंतर्गत, एक बीच ट्यूब-वेन और उसके जुड़ी यन्त्राइन के साथ 1,00,000 बैटन क्षमता वाली एक RCC ओवरहैड टैंक की व्यवस्था करने जैल आर्गुमें को बढ़ाना।
अनुमानित लागत (₹ में): 2,06,62,518.21 अव्ययत राशि (₹ में): 4,13,300.00
निविदा बंद होने की तिथि: 18.11.2026 को 10.00 बजे।
कार्य समापन की अवधि: 12 मही।
कार्य की प्रकृति: RCC OMT के निर्माण सहित कोई भी सिलित इंजीनियरिंग कार्य।
नोट:- 1. पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेलवे वेबसाइट www.irps.gov.in पर देखें। 2388/26 (PH)
 North central railways CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

सम्पादकीय.....

मर्ज का वाजिब खर्च

अक्सर मरीजों द्वारा उपचार के दौरान मनमाने दाम वसूलने और कीमतों में पारदर्शिता के अभाव के आक्षेप लगाये जाते रहे हैं। ये केवल पांच सितारा अस्पतालों के संदर्भ में ही नहीं है, क्लिनिकों,सरकारी अस्पतालों में उपचार के दौरान उपचार खर्च में पारदर्शिता के अभाव का जिक्र होता है। जो अकसर कमजोर वर्गों व निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के लिये रोग से बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इस समस्या के मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों और क्लीनिकों में स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं। निस्संदेह, इसे सरकार की ओर से एक अधिक पारदर्शी और मरीजों के अनुकूल व्यवस्था बनाने की दिशा में यह स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है। अकसर देखने में आता है कि इलाज के लिये आने वाले मरीजों को उपचार में होने वाले खर्च की स्पष्ट जानकारी नहीं होती। इसमें दो राय नहीं कि परामर्श शुल्क, जांच यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, इलाज की प्रक्रियाओं और अस्पताल में उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी होने से मरीजों को सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। साथ ही वे अचानक सामने आने वाले वित्तीय बोझ से बच सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुख्य सचिवों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। दरअसल, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स(केंद्र सरकार) नियम 2012 के तहत अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी सेवाओं और सुविधाओं के शुल्क को ऐसी जगह प्रदर्शित करें,जहां मरीज व उनके तिमारदार आसानी से देख सकें। सेवाओं व सुविधाओं की फीस अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में लिखी होनी चाहिए। हालांकि, इससे बचाव के को लेकर सरकारी व निजी अस्पतालों के संचालकों की दलील है कि उपचार की कीमतों की तय सीमा निर्धारित किए जाने से उपचार की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। दरअसल, कई प्राइवेट अस्पताल व क्लिनिकों के संचालक इन निर्देशों को लागू करने के बाबत तमाम तरह के किंतु–परंतु गिनाते हैं। उनकी दलील है कि इन नियमों को लागू करने से उपचार की आर्थिक व्यवहार्यता कमजोर हो सकती है। जिसके चलते उपचार की परिचालन लागत, बुनियादी ढांचे और क्लिनिकल विशेषज्ञता में अंतर को नजरअंदाज किया जा सकता है। निस्संदेह, इन चिंताओं पर विचार तो जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें कीमतों से जुड़ी जरूरी जानकारी छिपाने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि एक अच्छी सुविधाओं वाले प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल की लागत संरचना में अंतर होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी, मरीजों को इलाज के लिये सहमति देने से पहले यह जानने का अधिकार तो होना ही चाहिए कि उनकी जेब कितनी ढीली होने वाली है। इसके साथ ही देश में मेडिकल या आयुष वीजा पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिये केंद्र सरकार का ‘पैकेज रेट’ पर जोर देना भी काफी महत्वपूर्ण है। जिससे विदेशी मरीजों से मनमाने चार्ज न वसूले जा सकें। देश में बढ़ते मेडिकल टूरिज्म के विस्तार के लिये भी यह जरूरी है कि उपचार की लागत में पारदर्शिता बनी रहे। इससे देश की विश्वसनीयता भी बढ़ सकती है। निश्चित रूप से उपचार शुल्क में पारदर्शिता लाने से इससे जुड़े तमाम विवाद कम हो सकते हैं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब नियमित निरीक्षण, शिकायत दर्ज करने की सहज–सुलभ व्यवस्था और नियमों का लगातार पालन न करने पर उचित दंड के जरिये इन निर्देशों को अमल में लाना चाहिए। सही सूचना देने में देरी, गलत जानकारी और कीमतों में अनिश्चितता मरीजों की परेशानी को और बढ़ा सकती है। इसमें दो राय नहीं कि मरीजों को न केवल इलाज की सुविधा समय पर मिलनी चाहिए, बल्कि इलाज के खर्च के बारे में भी सही और भरोसेमंद जानकारी तो मिलनी ही चाहिए। यह हमारे चिकित्सा तंत्र में भरोसा बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

विमर्श

भारत की ताकत एकरूपता नहीं, विविधता है

प्रेरणा

हाल ही मैं अपने घर की दो महिलाओं के साथ घूमने के लिए मलेशिया गई थी। एक दिन निकले कहीं तो टैक्सी वाले ने सहजता से पूछारू किस मुल्क से आए हैं आप लोग? जैसे ही हमने कहा— इंडिया, वह खिल उठा—अच्छा, तो आप एसआरके के देश से आए हैं! इसके बाद तो उसने मुस्क्रुते हुए अपनी बेबाक टिप्पणियों से ऐसे शब्द—बाण चलाए कि हममें से कोई उसका प्रतिकार नहीं कर सका। उसने बताया कि ट्वेल्थ फ़ेल उसकी पसंदीदा फिल्म है और उसने एक चुभता हुआ सवाल भी दागा— श्क्या भारत में आज भी जातिवाद है? हिंदी फिल्मों में इसे देखकर दिल बैठ जाता है। टैक्सी में बैठी जेन—जी बेटी ने थोड़ा बचाव करते हुए कहा— जातिवाद है तो सही, पर शहरों में अब यह तेजी से खत्म हो रहा है। हम बड़े चुप ही रहे। ड्राइवर यहीं नहीं रुका, उसने भारत में महिला सुरक्षा और बलात्कार की घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह बेहद दुखद और शर्मनाक है क्योंकि महिलाओं का तो सम्मान होना चाहिए। हम उसकी बात

से इन्कार नहीं कर सकीं, पर बेटी फिर बचाव में उतरीरू लेकिन मुंबई बेहद सुरक्षित है! हमारे टैक्सी से उतरते—उतरते उसने कुछ ऐसा कहा कि हमने उसके सारे तीखे बोल भुला दिए, और हमारा दिल जीत लिया। उसने बेहद हैरान होकर कहा— लेकिन श्भारत का असली चमत्कार तो यह है कि इतनी भिन्नताओं, विविधताओं और अलग—अलग मजहबों के बावजूद वहां कभी कोई गृह युद्ध नहीं होता! एक विदेशी हमारे देश की ऐसी विशेषता को पहचानता भी है और इतनी समझदारी से बताता भी है, यह सुनकर हम सभी विस्मित भी रह गए और भारतीय होने के गर्व से भर भी गए। उस सामान्य—से टैक्सी वाले की यह कोई सामान्य—सी टिप्पणी नहीं है। हम भारतीय भी इसे गहराई से समझते नहीं हैं। यह हमारे देश की अद्भुत सामाजिक संरचना है कि जहां परस्पर विरोधी विचारधाराएं भी सह—अस्तित्व में रहती हैं। कई लोग इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं लेकिन मुझको लगता है यह वाद से कहीं आगे की मनोभूमिका है। वाद तो सिद्धांत को दर्ज करते हैं, समाज जब उनको

व्यवहार में उतारता है तब वह बहुत नया व गहरा बन जाता है। सत्य, अहिंसा और करुणा की त्रिवेणी से सुजला—सुफला की इस भूमि पर सदभाव की अविरल धारा बहती रही है। विदेशी आक्रांता अपने साथ अपनी धार्मिक रूढ़ियां लेकर आए जरूर मगर हमारे समाज ने उन्हें भी अपने में समो लिया। ये भी हमारी साझा संस्कृति के हिस्से बन गए। उनका भारतीय संस्करण कुछ अलग ही तज से तैयार हो गया। इतिहास में कई बार इस ताने—बाने पर खतरे मंडराए, लेकिन अनेकांतवाद के अदृश्य कवच ने भारत को हमेशा सुरक्षित रखा। इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रवेश के साथ एक—दूसरे तरह की वैचारिक व व्यावहारिक चुनौती सामने आई। ये दोनों ही संगठित और एकेश्वरवादी धर्म थे। इनका मानना था कि केवल उनका ईश्वर और उनकी पद्धति ही सत्य है और उन्हें इस सत्य से सारी दुनिया को सहमत करवाना है। ऐसी कहरता से हमारा सामना पहली बार ही हुआ। लेकिन हमने देखा कि उनकी धार्मिक कहरता भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने तरल होती गई और वक्त के

साथ—साथ उनका भी भारतीयकरण होता गया। इन धर्मों का आक्रमक कहरपंथ धीमा पड़ता गया। गंगा—जमुनी तहजीब की एक नई लहर फैलती गई। इतिहास ने देखा कि भारत की मिट्टी में नफरत को मोहब्बत में बदलने का एक अनूठा रसायन सक्रिय रहता है। बीसवीं सदी में इसके समानांतर एक बार फिर हिंदू कट्टरपंथ उभरा, जिसका एकमात्र लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना था। स्वतंत्रता के समय जब त्रावणकोर को भारत से अलग संभ्रभु राष्ट्र बनाने की आवाज उठी, तो आरएसएस और हिंदू महासभा ने इस मांग का समर्थन किया। हिंदुत्व की विचारधारा की ऐसी संकीर्ण व्याख्या ने हमारे भीतर नया विभेद पैदा कर दिया। यहां से जो जहर बना व फैला वही देश को विभाजन तक पहुंचा गया। विभाजन का विनाशकारी परिणाम और अमानवीय हिंसा इसी अतिवादी सोच की संतान थे। विखंडन वाला वही वैचारिक कुनबा आज अखंड भारत का खोखला नारा देकर जनता को भ्रमित करना चाहता है। अखंड भारत जैसी कल्पना का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है।

अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग

बेटी बचाने के नारे गढ़ने वाले, लड़कियों के मुंह से अपशब्द सुनकर सांस्कृतिक झटका खाने वाले, नवरात्रि में शक्ति की आराधना के लिए पूरे नौ दिन व्रत रखने का दावा करने वाले नरेन्द्र मोदी ने एक 19 बरस की मासूम लड़की की नृशंस हत्या पर इंसाफ मांगने वाले उसके मां–बाप पर जो जुल्म ढाया है, उसे देश भूलेगा नहीं। सितंबर 2022 में उत्तराखंड के ऋषिकेश के पास वनतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। 18 सितंबर को अंकिता लापता हुई और छह दिन बाद 24 सितंबर को उसका शव चिल्ला नहर से बरामद हुआ। पता चला कि रिजॉर्ट के मालिक कुछ खास लोगों की सेवा करने का दबाव अंकिता पर बना रहे थे। साफ शब्दों में कहें तो उसे यौन उत्पीड़न के लिए खुद को प्रस्तुत करने कहा जा रहा था।



उसमें पीड़ितों के हिस्से में सजा और प्रताड़ना देने वालों को इनाम मिलता है। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई 2022 से अनवरत चल रही है। राज्य सरकार ने इसमें एसआईटी गठित की। इसमें तीन मुख्य आरोपियों पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को मई 2025 में दोषी ठहराया गया और अब वे जेल में उम्र कै द की सजा काट रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम भी सामने आया, जिन्हें अब मोदी सरकार ने सिविकम

का राज्यपाल बनाया है।

गोरतलब है कि अंकिता की हत्या के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज

लेकिन अब दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाकर उन्हें जांच से बचाने का दांव शायद भाजपा ने चल दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की कौन सी



करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। दर्ज शिकायत के अनुसार, दुष्यंत गौतम ने आरोप लगाया था कि हरिद्वार के ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उनके खिलाफ सुनियोजित आपराधिक साजिश रची थी। लेकिन अब तक इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आई है कि दुष्यंत कुमार सही कह रहे हैं, या उन पर आरोप लगाने वालों ने सच कहा है। इसके लिए निष्पक्ष जांच की जरूरत होती है।

मजबूरी थी जो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या भाजपा में कोई और नेता नहीं था, जिसे मोदी–शाह उपकृ त करते। क्या मोदी–शाह नहीं जानते थे कि दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाने पर सवाल उठेंगे ही, लेकिन फिर भी उन्होंने यह फैसला लिया तो क्या इसके पीछे सत्ता पर बने रहने का घमंड है या सारे संस्थानों पर कब्जा करने का। क्या मोदी–शाह यह मानते हैं कि कोई कितना भी विरोध कर ले, उनका कोई कुछ नहीं

राजाओं ने अपने साम्राज्यों का विस्तार जहां तक किया हो, क्या उनसे कोई राष्ट्र निर्मित होता है? फिर तो कोई हिटलर उन सबको अखंड जर्मनी घोषित कर देगा जिसे उसने युद्ध के मैदान में हराया था। यह सब इतिहास को देखने की बीमार दृष्टि है।

जो शक भी पैदा करती है और विग्रह भी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत यही सब लेकर अभी–अभी विदेशी मंत्रों पर पहुंचे थे और बुरी तरह अस्वीकृत हो कर लौटे हैं। यह हम सबके सोचने व समझने की बात है कि भारतीय समाज के आंतरिक विभाजन को चौड़ा करने की तमाम साम्राज्यवादी कोशिशों और विषवमन के बावजूद 1947 में केवल दो हिस्सों की क्यों बंटा? मांग तो सिखों की भी थी, दक्षिण की भी थी, पूर्वोत्तर के राज्यों की भी थी। वैसी सारी प्रवृत्तियों को समझा कर, मना कर देश की राजनीतिक–भौगोलिक एकता को एकजुट करना कैसे संभव हुआ था? इसका पूरा श्रेय महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व को जाता है। गांधीजी ने आजादी की लड़ाई की रचना ऐसे की कि जाति,

धर्म, भाषा, लिंग और आयु की दीवारें ढहती गईं और एक हिंदुस्तानी मन उभर कर सामने आने लगा। हर हिंदुस्तानी

स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही बनने लगा। उन्होंने पूरे देश को एक साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ना और एक बहुसांस्कृतिक समाज में आपसी सदभाव के साथ जीना सिखलाया। ऐसी ही कोशिश में उनका बलिदान भी हुआ लेकिन जवाहरलाल, पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र बाबू आदि के सम्मिलित नेतृत्व ने गांधी की उस दिशा से देश को भटकने नहीं दिया।

जो कभी स्वातंत्र्य संग्राम के सिपाही नहीं रहे, जिन्होंने ऐसे भारत की कल्पना में कभी साझेदारी नहीं की, जिन्होंने विभाजन और नफरत की राजनीति को अपना हथियार बनाया। उन सबको यह भारत कभी समझ में नहीं आया। महात्मा गांधी ने एक रास्ता दिखलाया। आधुनिक विश्व की समस्याएं भी नई हैं जिन्हें आधुनिक नजरिये से हल किया जा सकता है। वह सब कुछ आधुनिक है जो मनुष्य को, देशों को निकट लाता है, उनमें परस्पर विश्वास बढ़ाता है।

अंधाधुनिकता का जहर फैला रहा है। अंधाधुनिकता का जहर फैला रहा है। अंधाधुनिकता का जहर फैला रहा है। अंधाधुनिकता का जहर फैला रहा है।

भंडारी की मां ने कहा कि जब तक दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द नहीं होती, तब तक वे विरोध करती रहेंगी। उन्होंने कहा, रहम ऐसे बैठे रहेंगे, चाहे हम अपने घर में रहेंगे। अगर हमें नहीं बैठने देंगे तो हम अपने घर में भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। वही अंकिता के पिता ने कुछ मांगें रखी हैं, जैसे अंकिता मामले में सीबीआई की पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त जज की सीधी निगरानी में कराई जाए। यह पता लगाया जाए कि वनतरा रिसॉर्ट को ध्वस्त करने का आदेश किसने दिया था और पुलकित आर्य के फोन की 18 और 19 सितंबर की कॉल डिटेल की बारीकी से जांच की जाए, ताकि पता चल सके कि वह किन–किन लोगों के संपर्क में था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का तो दावा है कि राज्य सरकार की एसआईटी जांच से इंसाफ मिल चुका है, लेकिन अगर अब भी पीड़िता के मां–बाप इसे इंसाफ नहीं मान रहे और कुछ मांगें रख रहे हैं, तो उन्हें मानने में सरकार को हर्ज क्यों होना चाहिए। मोदी–शाह अगर जनता की नाराजगी और उसकी अपेक्षाओं को इसी तरह नजरंदाज कर सत्ता की अकड़ दिखाते रहे तो यह समूची भाजपा को दूरगामी नुकसान पहुंचाएगा।

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कैसे बहाल होगी

राजेश पांडेय

लम्बे समय बाद भारत में विपक्षी दलों को किसी एक मुद्दे पर एकजुट होते देखा गया है। 12 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, एसआईआर को रद्द करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट तक कूच किया। इसके बाद कूच में शामिल वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने देश की शीर्ष अदालत में दाखिल संयुक्त याचिका में ये मुद्दे उठाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सभी विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक ही प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एक देश, एक चुनाव के मुद्दे का जवाब है। 2014 के बाद पहली बार विपक्ष को किसी एक मुद्दे पर पूरी ताकत से एक साथ आवाज उठाते देखा गया है। अब तक विपक्षी दल राज्यों में अपने हित्तों के हिसाब से अलग–अलग संघर्ष करते रहे हैं। चुनावों के समय स्थानीय स्तर पर गठबंधन हो जाते हैं। कई बार संसद में कुछ मुद्दों पर एकता नजर आती है। लेकिन इस मर्तबा चुनावों में धांधली के मुद्दे ने विपक्षी नेताओं को अपने मतभेद, महत्वाकांक्षा और अहंकार से परे हटकर साथ आने के लिए मजबूर किया है। विपक्ष को अहसास हो गया है कि यदि चुनाव आयोग के खिलाफ मिलकर अभियान नहीं चलाया गया तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने मैदानी संघर्ष और कानूनी लड़ाई में साथ रहने का रणनीतिक फैसला लिया है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संकट के बीच यह घटनाक्रम अच्छा संकेत है। चुनाव आयोग करोड़ों वोटरों का हक छीन रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक हस्तक्षेप करने की जरूरत

नहीं समझी थी। उसने बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि पूरी प्रक्रिया कानून की दृष्टि से जायज है। एसआईआर कानूनन जायज तो है लेकिन उसका तरीका गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा कि जो काम एक–दो साल में होना चाहिए वह चुनाव से कुछ माह पहले जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है। अब यह मुद्दे जनता के दिल–दिमाग पर दस्तक देने लगे हैं। कॉर्कोरच जनता पार्टी की मुहिम बताती है कि युवाओं का एक वर्ग भी चुनावों में धांधली के मुद्दे पर आंदोलित है। राजनीतिक दलों ने इसे और अधिक स्पष्ट और पैना बना दिया है। एसआईआर में धांधली के बारे में एक और खुलासा सामने आया है। चुनाव विश्लेषक प्रणव राय ने मई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर एसआईआर के प्रभाव का विश्लेषण किया है। उसके अनुसार जिन 25 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मतदाता हटाए गए हैं, उनमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट रिवंग 10.5 प्रतिशत हुआ है। जिन क्षेत्रों में सबसे कम वोटर बाहर हुए हैं, वहां तृणमूल के खिलाफ केवल 5.3 प्रतिशत वोट रिवंग रहा। पिछले चुनाव नतीजे बताते हैं कि तृणमूल को महिला और मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा समर्थन मिलता रहा है। तृणमूल को महिलाओं के वोट भाजपा से 43 प्रतिशत ज्यादा मिले हैं। बंगाल में पुरुष और महिला वोटरों की संख्या लगभग बराबर है। लेकिन एसआईआर में महिलाओं के 62 प्रतिशत और पुरुषों के केवल 38 प्रतिशत वोट कम हुए हैं। राज्य में पिछले चुनावों में तृणमूल को मुसलमानों के 75प्रतिशत और भाजपा को 7–8प्रतिशत वोट मिले हैं। एसआईआर में गैर–मुसलमानों के मुकाबले मुसलमानों के 52प्रतिशत वोट

ज्यादा बाहर हुए हैं। यह विश्लेषण पूरी प्रक्रिया को संदेह के दायरे में खड़ा करता है। लगता है, जानबूझकर महिला और मुस्लिम वोटरों को बाहर किया गया है। दो चुनाव आयुक्तों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त मनमानी से पर्दा हटाने के बाद आयोग ने कुछ सुधार किए हैं। दोनों आयुक्तों ने नए वोटरों को शामिल करने के फार्म 6 में अतिरिक्त घोषणा को गैरकानूनी बताया था। इसे पिछले दरवाजे से नागरिकता साबित करने की कार्यवाई मानी जा रही है। फार्म 7 के जरिये थोक में वोटरों को हटाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। यह फार्म किसी वोटर का नाम हटाने या किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में शामिल करने पर आपत्ति जताने से संबंधित है। कई राज्यों में फार्म 7 के दुरुपयोग की शिकायतें आई हैं। उसके खिलाफ आंदोलन हुए हैं। 9 अक्टूबर को आयोग ने स्वीकार किया कि थोक में फार्म 7 दाखिल किए जाने से वोटरों को असुविधा हुई है। अब आयोग ने प्रति व्यक्ति यह फार्म जमा करने की संख्या दस तक सीमित कर दी है। एसआईआर शुरू होने के बाद कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना और उड़ीसा में राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर थोक में फार्म 7 जमा करने के आरोप लगाए थे। सितंबर में बीजू जनता दल ने उड़ीसा के मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने मामला उठाया था। बृथ लेवल के कुछ अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कि उनकी जानकारी के बिना उनके नाम से फार्म 7 दाखिल किए गए हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक अधिकारी को हटाया था। चुनाव आयोग की अनियमितताओं का सिलसिला अनंत है। उसने चुनाव आचार समितिता उल्लंघन के मामले में सत्ताधारी दल और विपक्ष के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है।

फातिमा बोलीं , किसी के शरीर पर बोलने वाले आप कौन?

फातिमा इन दिनों अपनी आगामी वेब सीरीज श्हुंकारश् को लेकर चर्चा में हैं। अमर उजाला से बातचीत में जब महिलाओं के खिलाफ होने वाली हालिया घटनाओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने जमुई मामले का जिक्र किया। बिहार के जमुई में बीते दिनों नाबालिग लड़की के साथ हुई घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और समाज की सोच पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आया था। अब अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। श्उस लड़के ने कमाल ही हिम्मत दिखाईश् फातिमा ने कहा कि 2026 में भी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होना बेहद दुखद है। वह बोलीं— ३17 साल की उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, वह पूरी तरह गलत था। वहां एक 17 साल का लड़का भी था, जिसने हिम्मत दिखाई, जो अच्छी बात है। लेकिन ऐसी घटना कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। वो बेचारी आइसक्रीम खाने गई थी। दुख की बात है कि आज हम 2026 में हैं और फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमें अ ा गे बढ ना च्छि।

आखिर ये कैसे घटिया हरकत है? ये बहुत ही नीच मानसिकता है।' श्बस इज्जत करना सीख जाएश् समाज में एक बदलाव लाने का मौका मिले तो वह किस तरह का बदलाव चाहेंगी? पूछा जाने पर फातिमा ने कहा, श्मुझे समाज में बहुत सारे बदलाव चाहिए। सभी जेंडर, जाति और वर्ग के बीच बराबरी होनी

चाहिए। अगर किसी दिन ऐसा हो पाया तो वही बहुत बड़ा बदलाव होगा। सबसे जरूरी है इंसान के लिए बुनियादी सम्मान। आप कहां से आए हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है? इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक—दूसरे की इज्जत करना सीख जाएं। इससे बड़ा बदलाव और कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अगर इंसान इतना सीख जाए तो आधी तकलीफ खत्म हो जाएगी।श् श्पुरुषों की मोरल पुलिसिंग शुरू करनी चाहिएश् महिलाओं की मोरल पुलिसिंग को लेकर भी फातिमा ने बेबाक राय दी। उन्होंने कहा, श्हमें महिलाओं की मोरल पुलिसिंग बंद करके पुरुषों की मोरल पुलिसिंग शुरू करनी चाहिए। इससे बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पुरुष खराब हैं। बहुत अच्छे पुरुष भी हैं, लेकिन महिलाओं की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। यह बहुत दुखद है।श् श्ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत बढ गई हैश् सोशल मीडिया पर महिलाओं की बॉडी शेमिंग को लेकर भी फातिमा ने चिंता जताई। हाल में मां बनने के बाद कटरीना कैफ को बॉडी शेमिंग का सामना करने के सवाल पर उन्होंने कहा, श्इन दिनों खासकर ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत ज्यादा बढ गई है। यह बहुत दुखद है। हाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां किसी को बॉडी शेम किया जा रहा है। किसी का शरीर कैसा होगा, यह तय करने वाले हम कौन होते हैं? कोई पतला है, मोटा है, बड़ा है या छोटा है, इससे किसी और को क्या लेना—देना? दुःख इस बात का भी है की इसमें सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी शामिल हैं। ३ श्वह खुद अपने ही पिंजरे में होंश् फातिमा से जब पूछा गया कि कई बार महिलाएं ही दूसरी महिलाओं को ट्रोल करती हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद इसके पीछे उनकी अपनी जिंदगी की परेशानियां भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा, श्पता नहीं वे ऐसा क्यों करती हैं। शायद उनकी अपनी जिंदगी में भी तो कुछ न कुछ चल रहा होगा। कई बार मैं सोचती हूं कि शायद उनकी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि वह खुद भी अपने ही पिंजरे में हों।श् लड़की के साथ हुई घटना पर अभिनेत्री का कड़ा रुख मीडिया से बातचीत करते हुए अभिनेत्री फातिमा ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि वर्ष 2026 में भी महिलाओं के साथ इस तरह के अपराध होना अत्यंत लज्जाजनक और दुखद है। उन्होंने कहा कि उस 17 वर्षीय बालिका के साथ जो कुछ भी हुआ, वह पूरी तरह से गलत और अस्वीकार्य था। हालांकि, उन्होंने इस दौरान उस 17 वर्षीय लड़के की सराहना भी की जिसने उस मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाई, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी अमानवीय घटनाएं किसी भी सूरत में किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। वह पीड़िता महज आइसक्रीम खाने के लिए बाहर गई थी। फातिमा ने रोष जताते हुए कहा कि आज हम इक्कीसवीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं होना और लोगों की नीच मानसिकता का परिचय देना बेहद चिंताजनक है। समाज में बुनियादी सम्मान और बराबरी की आवश्यकता जब अभिनेत्री से यह पूछा गया कि यदि उन्हें समाज में कोई बदलाव लाने का अवसर मिले, तो वह किस प्रकार का परिवर्तन चाहेंगी? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि उन्हें समाज में अनगिनत बदलावों की आवश्यकता महसूस होती है। समाज में सभी जेंडर, जातियों और वर्गों के बीच पूर्ण समानता होनी चाहिए। यदि किसी दिन यह बराबरी स्थापित हो सकी, तो वही सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हर इंसान के लिए बुनियादी सम्मान (बेसिक रिस्पेक्ट) है। व्यक्ति कहां से आया है या उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, इस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि लोग केवल एक—दूसरे का सम्मान करना सीख जाएं, तो समाज की आधी से ज्यादा समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। महिलाओं के बजाय पुरुषों की मॉरल पुलिसिंग की जरूरत महिलाओं पर होने वाली तथाकथित श्मॉरल पुलिसिंग पर बेबाक राय रखते हुए फातिमा ने कहा कि हमें महिलाओं पर सवाल उठाने और उनकी नैतिकता तय करने की परंपरा को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत, अब पुरुषों की मॉरल पुलिसिंग शुरू करने की आवश्यकता है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकें।



पैर की हड्डी टूटी थी, चोट के निशान थे- दावा

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक्टर के पोस्टमार्टम से जुड़ा बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के समय सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई, आंख के पास चोट के निशान थे और गले में स्टेन गन के भी निशान बने हुए थे। श्वेता सिंह कीर्ति ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो जारी कर कहा— 'आप सब जानते हैं कि जो भाई के साथ हुआ वो गलत है। हमें कुछ समय पहले ही पता चला है कि भाई का पोस्टमार्टम करने वाले शख्स ने कहा है कि उस पर स्टेन गन इस्तेमाल हुई थी। उसके पैर टूटे हुए थे। उस पर काफी सारा फोर्स लगाया गया था। आंखों में भी चोट आई थी।' आगे श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा, 'आप लोगों को लगता है कि भाई के साथ जो हुआ वो गलत था, जाहिर तौर पर गलत था। हम सब दिलों में जानते हैं कि जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि मैं उसकी बहन हूं, मैं जानती हूं कि ये कैसा लगता है कि हमारे किसी करीबी से साथ ऐसा कुछ हुआ है। जब ये हमारे साथ हो, तो हम माफ कर सकते हैं, लेकिन किसी अपने के साथ ऐसा हो तो ये भूलने के लिए काफी हिम्मत लगती है।' श्वेता ने वीडियो के आखिर में लोगों से अपील की है कि वो नफरत या बदले की भावना न रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी फैंस भगवान पर भरोसा रखें। वीडियो के कैप्शन में श्वेता ने लिखा है, 'मैं ये नहीं कह रही हूं कि न्याय और सही के लिए लड़ाई मत करो, मैं कह रही हूं कि इसे प्यार की भावना के साथ करें बदले की भावना के साथ नहीं।' बता दें कि श्वेता सिंह कीर्ति में कहीं भी साफ नहीं किया है कि पोस्टमार्टम करने वाले शख्स ने उनसे या किसी एथॉरिटी से बात की है या नहीं। ना ही उन्होंने इन दावों से जुड़े कोई साक्ष्य दिखाए हैं। दैनिक भास्कर उनके दावों की पुष्टि नहीं करता है। ब्प जांच में मौत को आत्महत्या करार दिया गया सुशांत सिंह राजपूत 14 जून, 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए थे।



स्वरा भास्कर का खुलासा

'शादी से पहले दो बार कराय़ा था IVF...'

राइज एंड फाल 2 रिएलिटी शो में नजर आ रही एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि वो सोचती थीं शादी तो होने से रही, इसलिए मैं अकेले ही IVF से बच्चा करने वाली थी... एक्ट्रेस ने इस सो में बात करते हुए कहा, मैं तो आईवीएफ कराने वाली थी. मैंने तो अपने पैरेंट्स को भी मना भी लिया था कि शादी तो होने से रही. तो मैं आईवीएफ से बच्चा करूंगी. काम के लिए बेटे को छोड़ना घर, अब परिणीति चोपड़ा का छलका दर्द हालांकि उनकी ये बात सुनकर उनके पैरेंट्स थोड़े परेशान हुए थे. एक्ट्रेस ने बताया, पैरेंट्स बहुत ही स्वीट हैं. उन्होंने कहा कि इंडिया जैसे देश में ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा. लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो करो. शादी से पहले दो बार IVF कराय़ा..., स्वरा भास्कर का चौंकाने वाला खुलासा एक्ट्रेस का कहना है— मैं सच में एक बच्चा चाहती थी और फेमिली बसाना चाहती थी. मैंने दो राउंड आईवीएफ कराय़ा भी था, एनॉनमस स्पर्म डोनर से. लेकिन हुआ नहीं. ३ उन्होंने ये भी बताया कि बाद में फहाद से दोस्ती हुई. दोनों ने तीन महीने डेट किया था. और फिर ऐसा हुआ. स्वरा ने कहा— श्हमने कोर्ट मैरिज की थी. उस वक्त हमें दो— दिन खुशखबरी एक साथ मिल गई थी. शादी से पहले दो बार IVF कराय़ा..., स्वरा भास्कर का चौंकाने वाला खुलासा आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने 6 जनवरी 2023 को समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद से कोर्ट मैरिज की थी. इसके बाद उन्होंने 16 फरवरी 2023 को शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट

की थी. उन्होंने दिल्ली में 16 मार्च 2023 को ग्रैंड रिसेशन का आयोजन किया था जिसमें राजनीति के कई दिग्गज लोग शामिल हुए थे. मनीष कश्यप ने की स्वरा भास्कर की तारीफ ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा चर्चा में आ रहा है. इसी दौरान मनीष कश्यप ने भी स्वरा भास्कर को लेकर अपनी राय रखी. मनीष ने कहा, श्मैंने उनके बारे में बाहर कभी कुछ नहीं कहा. उनकी विचारधारा मुझे पसंद नहीं है. उन्होंने एक दो बार ट्वीट वगैरह कर दिया था.जब मैं जेल गया था तो मेरे खिलाफ पोस्ट किया था. बुरे समय में मैं किसी को ट्रोल नहीं करता हूं. मेरी ऐसी आदत नहीं है. शादी से पहले दो बार IVF कराय़ा..., स्वरा भास्कर का चौंकाने वाला खुलासा इसके बाद तारीफ करते हुए कहा, लेकिन सच बोलना चाहिए. स्वरा बहादुर लेडी हैं.नॉलेज है आइडिया है. सब कुछ है. अपनी बातों को दमदार तरीके से रखती हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें कर देती हैं कि सारी चीजें खत्म हो जाती हैंश् आपको बता दें कि ये रिएलिटी शो प्राइम वीडियो और एमएक्सप्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है. इसे आप हर रोज दोपहर 12 बजे देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस रिएलिटी शो को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं. इसमें 15 कंटेस्टेंट हैं. लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले शहजाद पूनावाला, स्वरा भास्कर और मनीष कश्यप, तेज प्रताप यादव बाकियों से ज्यादा फुटेज ले रहे हैं. उनके अलावा इस शो में गौतम गुलाटी, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी, कायरा, इरिना रुझाकोवा, अनीश भगत, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, काजल राघवानी, राज ग्रोवर् है.



जपाल यादव ने जमा किए 2 करोड़ रुपए, अब विदेश में कर सकेंगे काम, कोर्ट ने पासपोर्ट लौटाने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजपाल यादव के लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। कोर्ट ने ध्यान दिया कि अभिनेता ने अपनी रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह यादव का पासपोर्ट वापस कर दे, ताकि वे विदेश में अपने पेशेवर काम के लिए जा सकें। हालांकि, इसके लिए उन पर कुछ शर्तें लागू होंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि जमा की गई रकम और दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखते हुए, इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ताओं (यादव और उनकी पत्नी) ने रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। उठाए गए मुद्दों को देखते हुए, हमें लगता है कि मध्यस्थता के जरिए इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे इस विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करेंगे। पीठ ने आदेश दिया, प्ध्दोनों पक्ष मध्यस्थ से संपर्क करें और पेश होने की तारीख तय करें। मध्यस्थ दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन पेश होने के लिए कह सकते हैं। याचिकाकर्ता नंबर 1 (यादव) को अपना पेशेवर काम जारी रखने की अनुमति देने के लिए, ट्रायल कोर्ट उनका पासपोर्ट वापस कर दे, लेकिन इसके साथ कोर्ट कुछ शर्तें भी लगा सकता है। याचिकाकर्ता (अभिनेता) को केवल उन शर्तों का पालन करते हुए ही यात्रा करनी होगी और वापस लौटने पर ट्रायल कोर्ट को सूचित करना होगा। यादव के वकील विक्रांत ने अदालत से आग्रह किया कि अभिनेता को एक पेशेवर काम के सिलसिले में कनाडा जाना है, और वहां जाने पर उन्हें कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। सुनवाई के दौरान, यादव के वकील ने बताया कि अभिनेता ने कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन करते हुए पूरे 2 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि चेक बाउंस के सात मामलों में उनकी सजा (तीन महीने की जेल) को चुनौती देने वाली याचिका पर गुण—दोष के आधार पर सुनवाई की जाए। श्भ्र ने शुरुआत में कहा कि कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों पक्षों से विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने पर विचार करने को कहा। सीजेपी ने प्रतिवादी से कहा, आप लोग अब इस विवाद को क्यों नहीं सुलझा लेते ? अगर आप समझदारी और निष्पक्षता से काम लें... तो हमारे पास 2 करोड़ रुपये जमा हैं। आपको भी समझदारी दिखानी चाहिए और मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। यादव के वकील ने बताया कि अभिनेता ने पैसों का इंतजाम करने के लिए अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेच दी है। हालांकि, ने कहा कि इस चरण में कोर्ट के दखल देने की गुंजाइश सीमित है। 7 अक्टूबर को, सीजेपी ने अभिनेता से एक अच्छी फिल्म बनाने, लोगों का फिर से मनोरंजन करने और अपनी छवि सुधारने के लिए कहा था। बेंच ने चेक बाउंस के लंबे समय से चल रहे मामलों में उनके द्वारा किए गए 1.15 करोड़ रुपये के भुगतान पर भी ध्यान दिया। यह कानूनी विवाद 2010 के एक वित्तीय समझौते से जुड़ा है, जिसमें यादव को अपनी पहली निर्देशित फिल्म श्शता पता लापताश् के लिए एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये मिले थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2013 में, यादव ने 2010 में फिल्म के लिए मिली 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को चुकाने के लिए 1.05 करोड़ रुपये के सात चेक दिए थे। फर्म का आरोप है कि ये चेक बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता के अनुसार, 2012 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी ने न्याज सहित लगभग 11 करोड़ रुपये चुकाने पर सहमति जताई थी। 15 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने यादव को सरेंडर करने से मिली छूट को 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। 8 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने यादव की याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि अगर वे कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा कर देते हैं, तो उन्हें सरेंडर करने से छूट मिल जाएगी।10 जुलाई को, दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के कई मामलों में यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि के खिलाफ याचिकाएं दायर करने में हुई 1,894 दिनों (यानी पांच साल से अधिक) की असाधारण देरी को माफ करने से इनकार कर दिया। साथ ही, कोर्ट ने यादव को निर्देश दिया कि वे सात अलग—अलग शिकायतों में से प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 1 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करें। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अभिनेता द्वारा पहले ही चुकाए गए लगभग 2 करोड़ रुपये को इसमें समायोजित कर लिया जाएगा। इसके अलावा, यादव को इस फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट में जाने का समय देने के लिए, कोर्ट ने सजा के अमल पर दो महीने के लिए रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने अभिनेता की पत्नी, राधा राजपाल यादव को भी आदेश दिया कि वे हर मामले में शिकायतकर्ता को ज़ुर्माने के तौर पर लगभग 5.5 लाख रुपये का भुगतान करें। कोर्ट ने कहा कि यदि वे ज़ुर्माना नहीं भरती हैं, तो उन्हें तीन महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी। हाई कोर्ट का यह फैसला यादव और उनकी पत्नी द्वारा दायर उन पुनरीक्षण याचिकाओं पर आया है, जिनमें उन्होंने सेशन कोर्ट के 2019 के फैसले को चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने अप्रैल 2018 में चेक बाउंस के मामलों में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाई गई उनकी सजा को बरकरार रखा था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिनेता को छह महीने की कैद की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में घटाकर तीन महीने कर दिया गया था।



सक्षिप्त



प्रियागोल्ड बिस्कुट में पशु चारे का उपयोग, एफएसएसएआई ने सूर्या फूड और डोडला डेयरी पर किया केस

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने प्रियागोल्ड बिस्कुट बनाने में पशुओं के चारे वाले चोकर का उपयोग करने के लिए सूर्या फूड एंड एग्रो के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के लिए डोडला डेयरी और यूईआईआर ऑर्गेनिक फूड्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की है। नियामक ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट में इन तीनों कंपनियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन को लेकर अभियोजन की कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी दी। एफएसएसएआई के अनुसार, प्रियागोल्ड बिस्कुट बेचने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो के संयंत्र का निरीक्षण उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद किया गया। कंपनी के निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आईं। नियामक ने कहा, “पशु चारे के लिए बने चोकर का इस्तेमाल प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने में फाइबर के स्रोत के तौर पर कच्चे माल के रूप में किया जा रहा था। यह चोकर इंसानों के खाने के लिए नहीं था।” एफएसएसएआई ने कहा कि चोकर से भरी बोरियों पर स्पष्ट रूप से अंकित था कि यह सामग्री पशु चारे के लिए है और मानव उपभोग के लिए नहीं है। इन गंभीर अनियमितताओं के बाद एफएसएसएआई ने पहले ही सूर्या फूड एंड एग्रो का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। अब कंपनी के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं, डोडला डेयरी के फुल क्रीम दूध का नमूना निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। खाद्य विश्लेषक ने दूध में वसा की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम होने के कारण नमूने को घटिया गुणवत्ता का घोषित किया था। कंपनी की अपील के बाद नमूने को रेफरल फूड प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया।

एक्सिस बैंक को दूसरी तिमाही में 7,704

करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ

निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने शनिवार को बताया कि वित्त वर्ष 2026–27 की दूसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 39.4 प्रतिशत बढ़कर 7,704.67 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ 5,527.85 करोड़ रुपये था। बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि एकल आधार पर उसका शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 37.6 प्रतिशत बढ़कर 7,003.28 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 5,089.64 करोड़ रुपये था। दूसरी तिमाही में बैंक का परिचालन लाभ छह प्रतिशत बढ़कर 11,083 करोड़ रुपये हो गया। बैंक का मुख्य परिचालन लाभ 11 प्रतिशत उछलकर 10,998 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में परिचालन लागत सालाना आधार पर नौ प्रतिशत बढ़ी। वित्त वर्ष 2026–27 की दूसरी तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 15,371 करोड़ रुपये रही, जो पिछली तिमाही से पांच प्रतिशत और सालाना आधार पर 12 प्रतिशत अधिक है। एक बयान के अनुसार दूसरी तिमाही में बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) 3.36 प्रतिशत रहा। बैंक का कुल ऋण 30 सितंबर, 2026 तक सालाना आधार पर 23 प्रतिशत और तिमाही आधार पर नौ प्रतिशत बढ़कर 13,73,727 करोड़ रुपये पहुंच गया। खुदरा ऋण सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 7,39,905 करोड़ रुपये रहा और कुल शुद्ध ऋण में इसकी हिस्सेदारी 54 प्रतिशत रही। समीक्षाधीन तिमाही में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात सुधरकर 1.16 प्रतिशत रहा, जो सालाना आधार पर 0.30 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 0.12 प्रतिशत कम है। शुद्ध एनपीए 0.35 प्रतिशत रहा, जो सालाना आधार पर 0.09 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 0.04 प्रतिशत कम है।

आईडीबीआई बैंक के विनिवेश पर वित्त मंत्रालय का बयान, कानून और अदालती फैसलों से बनी नीति

वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003 का विधायी इतिहास, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले और लगातार आम बजट भाषण से आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश की दिशा में सरकार की नीति के क्रमिक विकास का पता चलता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को लगभग 53,000 करोड़ रुपये में आईडीबीआई बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी थी। यह सौदा भारत के वित्तीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश और देश के बैंकिंग निजीकरण अभियान में एक बड़ा मील का पथर है। आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सेदारी घटाने से संबंधित विधायी घटनाक्रमों पर एक स्पष्टीकरण में मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2018 को फैसला सुनाया था कि आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003 में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में सरकारी हिस्सेदारी कम करने पर कोई रोक नहीं है। उल्लेखनीय है कि आम बजट 2003 की चर्चाओं और आईडीबीआई (निरसन) अधिनियम, 2003 पर संसदीय बहस के दौरान सरकार ने एक संशोधन पेश किया था, जिसमें सरकारी हिस्सेदारी में कमी को सीमित करने की बात कही गई थी। हालांकि, यह संशोधन खारिज हो गया था और लागू कानून का हिस्सा नहीं बन सका था। इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ तथा अन्य मामले में 17 दिसंबर, 2018 को फैसला सुनाया कि आईडीबीआई निरसन अधिनियम, 2003 की भाषा में कोई अस्पष्टता नहीं है और उक्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान जोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है।

जो सरकार को आईडीबीआई लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी कम करने या बेचने से रोकता हो। संसद में लगातार पेश किए गए बजट भाषणों में भी आईडीबीआई बैंक के कायाकल्प और रणनीतिक विनिवेश को लेकर सरकार की नीति को दोहराया गया था। वित्त वर्ष 2016–17 के आम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि आईडीबीआई बैंक के कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

खेल

मुंबई इंडियंस के साथ खत्म हुआ 10 साल का सफर, हेड कोच पद से हटे महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने ने 2027 सीज़न से पहले मुंबई इंडियंस के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। फ्रेंचाइजी के साथ अपने एक दशक लंबे जुड़ाव और दो कार्यकालों के दौरान उन्होंने टीम को तीन IPL खिताब जिताए। जयवर्धने ने इस शानदार सफर के लिए टीम प्रबंधन, खिलाड़ियों और अंबानी परिवार का आभार जताया। महेला जयवर्धने ने 2027 सीज़न से पहले इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। जयवर्धने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान पिछले दो सीज़न तक हेड कोच रहे, इससे पहले वे 2017 से 2022 तक भी इस पद पर रह चुके थे। फ्रेंचाइजी ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मुंबई इंडियंस ने आज घोषणा की है कि महेला जयवर्धने हेड कोच का पद छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही #OneFamily के साथ उनका एक दशक लंबा जुड़ाव समाप्त हो गया है। हेड कोच

के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मुंबई इंडियंस ने तीन IPL खिताब जीते। फ्रेंचाइजी ने जयवर्धने को टीम की संस्कृति को आकार देने और अनुशासन, आपसी सहयोग तथा टीम को सबसे पहले रखने (टीम-फर्स्ट अप्रोच) वाली सोच पर आधारित टीम का माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाने का श्रेय दिया है। मुंबई इंडियंस ने कहा, 2017 से 2022 तक और फिर 2024 से 2026 तक, इस भूमिका में अपने दो कार्यकालों के दौरान, उन्होंने फ्रेंचाइजी की संस्कृति को आकार देने, टीम का एक मजबूत माहौल बनाने और अनुशासन, आपसी सहयोग तथा शटीम को सबसे पहले रखनेश की सोच को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। जयवर्धने ने दस साल से अधिक समय तक इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, प्रशंसकों और मालिकों – नीता अंबानी तथा आकाश अंबानी –



को उनके समर्थन और भरोसे के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें टीम की उपलब्धियों पर गर्व है और उन्होंने भविष्य के लिए मुंबई इंडियंस को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से भी अधिक समय से मुंबई इंडियंस मेरे सफर का एक

बहुत ही खास हिस्सा रही है। खिलाड़ियों, कोचिंग टीम, #OneFamily (एक परिवार) के शानदार समर्थन और सबसे बढ़कर प्रशंसकों ने मिलकर इसे एक ऐसा अनुभव बना दिया है जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। हमने साथ मिलकर कुछ

अविस्मरणीय पल बिताए हैं, चुनौतियों का सामना किया है और कुछ ऐसा बनाया है जिस पर हम सभी को गर्व हो सकता है। मैं श्रीमती नीता अंबानी और आकाश अंबानी को इतने वर्षों तक मुझ पर अटूट भरोसा जताने, समर्थन देने और दोस्ती निभाने के लिए

दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने साथ मिलकर जो कुछ भी हासिल किया है, उस पर मुझे बहुत गर्व है और मेरे दिल में MI के लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी। मैं आने वाले वर्षों में टीम की सफलता की कामना करता हूं।

शुभमन गिल की रणजी ट्रॉफी में वापसी, वनडे में दोहरा शतक जड़ने के बाद मैदान पर

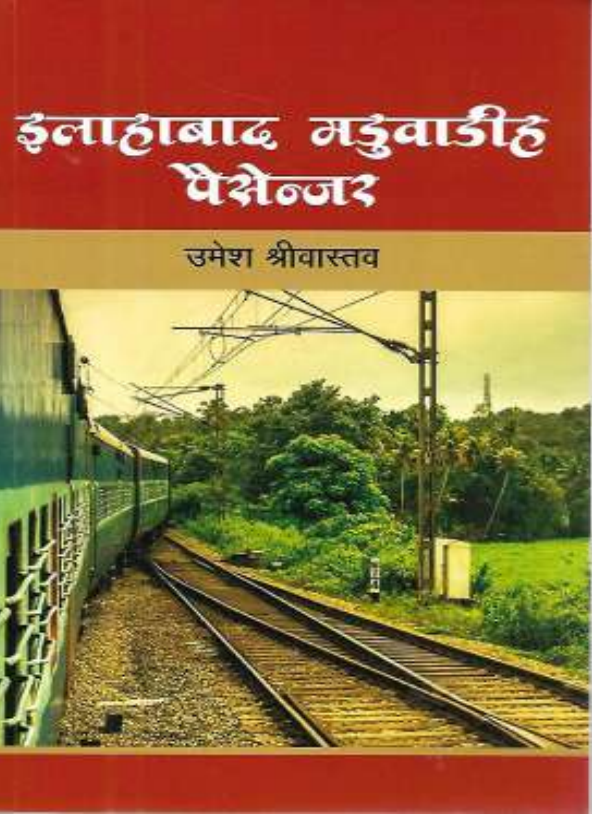
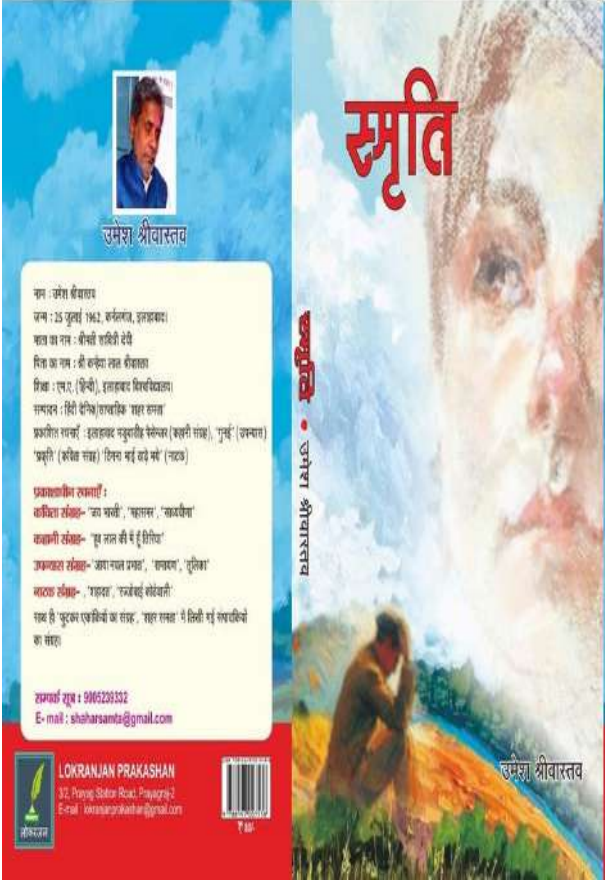
भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की पंजाब की तरफ से रणजी ट्रॉफी में वापसी रविवार से देशभर में शुरू होने वाले इस घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट के दूसरे दौर का मुख्य आकर्षण होगी। गिल पंजाब के पहले दौर के मैच में नहीं खेल पाए थे। उनकी अनुपस्थिति में भारत की अंडर19 टीम के पूर्व कप्तान उदय सहारन ने टीम की कप्तानी की। इस मैच में पंजाब ने असम के खिलाफ पहली पारी में बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए थे। सत्र के दूसरे दौर में पंजाब का सामना छत्तीसगढ़ से होगा। गिल का हाल में प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे श्रृंखला में 334 रन बनाए। गिल ने दूसरे वनडे में 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन बनाए और इस प्रारूप में सबसे तेज दोहरा शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ग्रुप बी के एक अन्य मुकाबले में कर्नाटक के ऑलराउंडर श्रेयस गोपाल के नेतृत्व में अलूर में सौराष्ट्र का सामना करेगा। इस मैच में उसे बल्लेबाज रविचंद्रन स्मरण की कमी खलेगी जिन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है। कर्नाटक को हालांकि चोट से उबरने वाले प्रमुख तेज गेंदबाज विद्वथ कावेरप्पा और वैशाक विजयकुमार की वापसी से

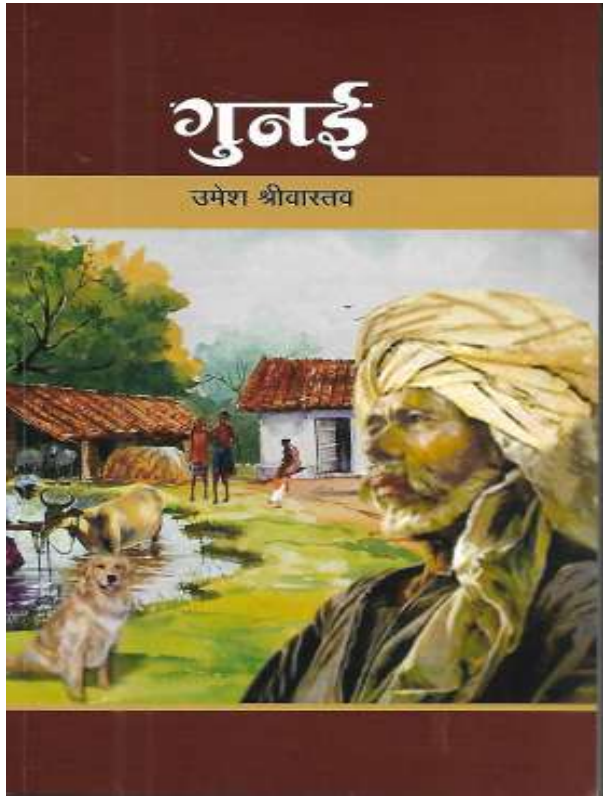
मजबूती मिलेगी। ग्रुप बी में शीर्ष पर काबिज हैदराबाद की टीम आंध्र के खिलाफ अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेगी। उसने पहले मैच में त्रिपुरा को पारी और 40 रन से हराकर बोनस अंक हासिल किया था। ग्रुप डी में मुंबई की टीम हिमाचल प्रदेश के खिलाफ उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे के बिना खेलेगी जो चोटिल हैं। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी इस मैच में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम का हिस्सा हैं। मुंबई ने दिव्यांश सक्सेना और अंगकृष रघुवंशी को टीम में शामिल किया है।

रणजी में शानदार प्रदर्शन के बाद भी शमी बाहर आकाश दीप की टेस्ट में वापसी

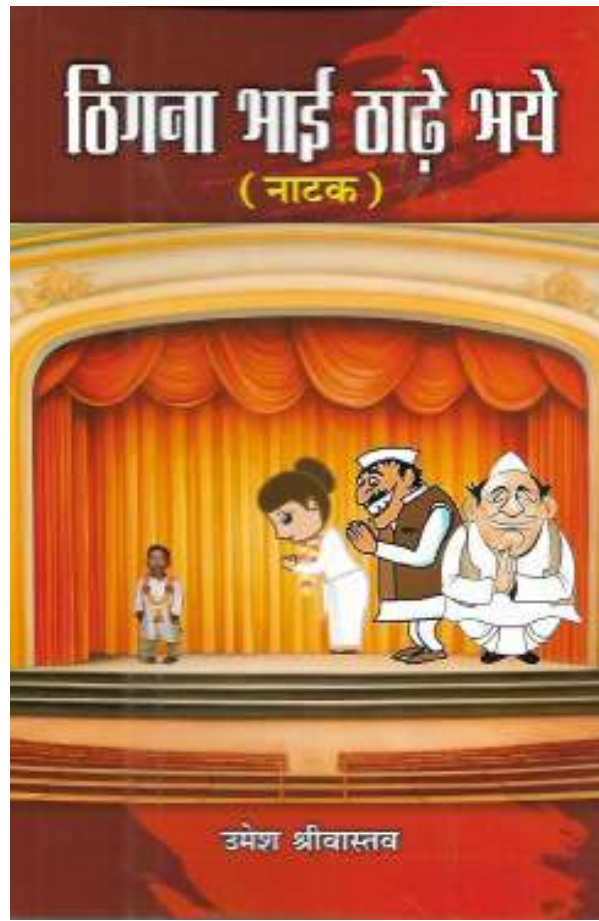
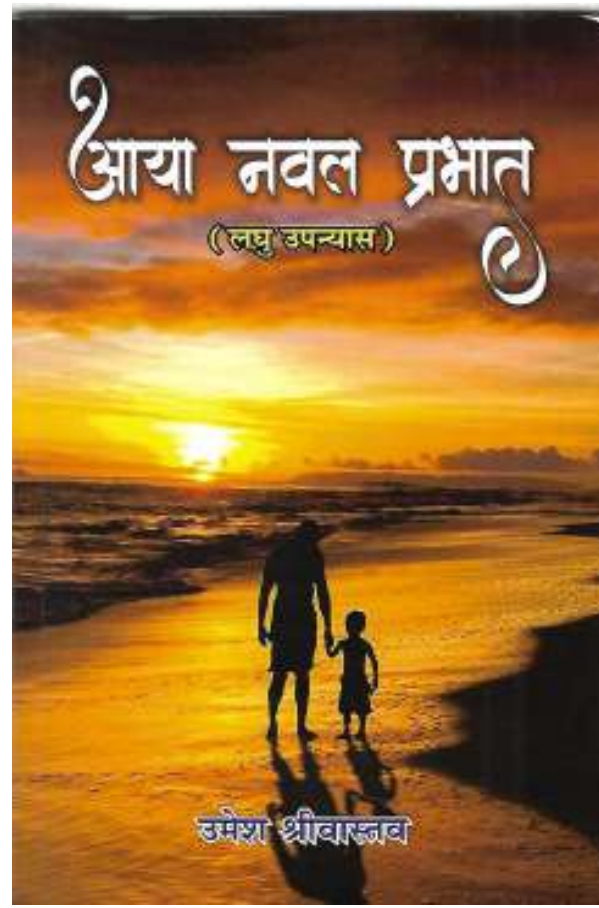
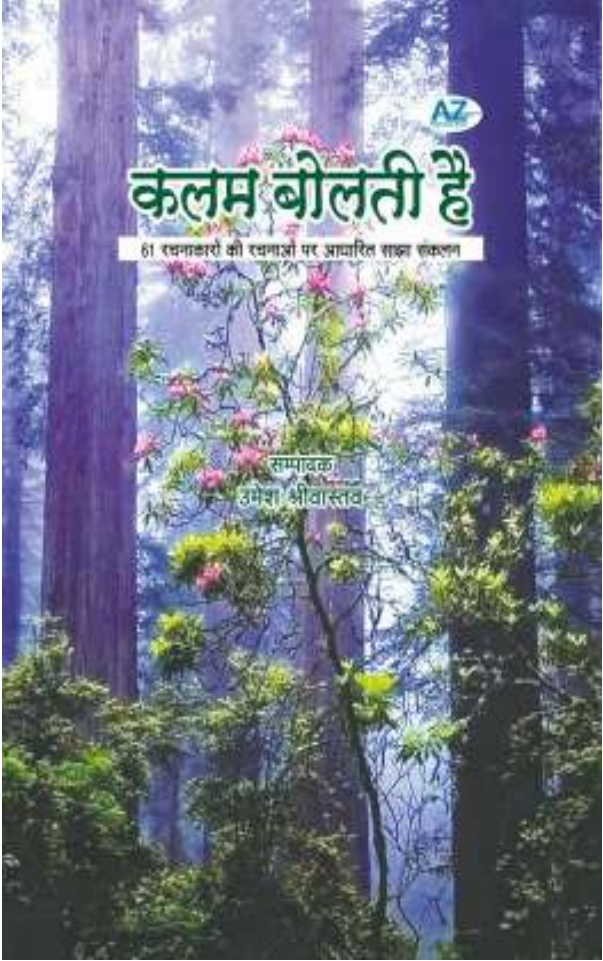
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट सीरीज के लिए घोषित राष्ट्रीय टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर शामिल नहीं किया है। 36 वर्षीय शमी ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लू चौपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेला था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने पांच पारियों में 25.88 की औसत से नौ विकेट लिए थे, जो भारत की जीत में अहम साबित हुए थे। उस मैच के बाद से, शमी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। 2026 दलीप ट्रॉफी में, उन्होंने तीन मैचों में 26.57 की औसत से सात विकेट लिए और ईस्ट जोन को खिताब जिताने में मदद की। 2025–26 रणजी ट्रॉफी सीज़न के दौरान, उन्होंने सात मैचों में 16.72 की औसत से 37 विकेट लिए। 2026–27 रणजी ट्रॉफी में अपने एकमात्र मैच में, शमी ने 4 / 30 और 1 / 29 के आंकड़े दर्ज किए। इंडियन प्रीमियर लीग (फ्रैं) में शमी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है; 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उन्होंने 9 मैचों में 6 विकेट लिए, और 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 13 मैचों में 12 विकेट लिए। घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए, उम्मीदें जगी थीं कि वे भारत की वनडे और टेस्ट टीम में वापसी करेंगे।



समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पेशेन्जर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।



चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित



ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

भारत पर 100% टैरिफ लागू होने से ठीक एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प का बड़ा यू-टर्न!

रूस से तेल पर लगे प्रतिबंध और शुल्क हटाए



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट (2026) के तहत रूस से तेल व गैस खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों, पाबंदियों और भारी शुल्कों (टैरिफ) को हटाने का एक बड़ा और अप्रत्याशित आदेश जारी किया है। यह फैसला ठीक उस समय आया जब 18 अक्टूबर से रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले भारत और चीन जैसे देशों के सामानों पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लागू होने वाला था। उन्होंने इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रीय हितरक्षक हवाला दिया है। शुक्रवार शाम को जारी एक कार्यकारी आदेश में ट्रम्प ने कहा, मैं ग्राहम एक्ट के तहत लगाए गए इन प्रतिबंधों, पाबंदियों और शुल्कों को हटा रहा हूँ। ट्रम्प ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस को एक प्रमाण—पर सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि यह छूट अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। लिंडसे ओ. ग्राहम एक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे मॉस्को पर कड़े प्रतिबंध लगा सकें और रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों (जिनमें भारत और चीन शामिल हैं) पर भारी

टैरिफ लगा सकें। ट्रम्प ने 18 सितंबर को श्याहम एक्ट पर हस्ताक्षर करके इसे कानून का रूप दिया था। इसका मकसद फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाना था। इसके तहत रूस के ऊर्जा क्षेत्र और रूस से तेल व गैस खरीदने वाले देशों को निशाना बनाया गया था। इस कार्यकारी आदेश के तहत, रूस से आने वाले सामानों पर शुल्क 500 प्रतिशत तक बढ़ सकता था। आदेश में यह भी प्रावधान था कि अगर रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात करने वाले पांच सबसे बड़े देश 18 अक्टूबर या उसके बाद जानबूझकर रूस से नई खरीदारी करते हैं, तो उनके सामानों पर 100: टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा,

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 5.7 तीव्रता का भूकंप

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के खुजुदार शहर से 48 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में था। फिलहाल भूकंप से हुए नुकसान या किसी के हताहत होने की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

होर्मुज और रोमानिया में दो टैंकों पर
हमला, सभी 24 भारतीय सुरक्षित

पश्चिम एशिया और रोमानिया में दो टैंकों को निशाना बनाया गया है। इन टैंकों पर सवार सभी 24 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि 16 अक्तूबर को होर्मुज जलडमरूमध्य में कच्चे तेल के एक टैंकर पर किसी प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इस पर 15 भारतीय नाविक सवार थे। इससे पहले 14 अक्तूबर को रोमानिया के सुलिना एंकरेज में एक केमिकल टैंकर ड्रोन हमले की चपेट में आ गया था, जिस पर 9 भारतीय नाविक थे। उन्होंने कहा कि दोनों जहाजों पर मौजूद सभी 24 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और किसी के हताहत या घायल होने की कोई सूचना नहीं है।

माकी रुबिया भारत दूरि में उठाए छत्र प्रदर्शनी
पर बल प्रयोग का मुद्दा: अमेरिकी सांसद

वाशिगटन,एन.सी। प्रमिला जयपाल और इल्हान उमर सहित छह अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो से आग्रह किया है कि वह भारत यात्रा के दौरान अपने भारतीय-समकक्षों के सामने दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में छात्र प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग के कथित आरोपों का मुद्दा उठाएँ। अमेरिकी सांसदों जयपाल, उमर, जिम मैकगर्गन, रशीदा तलाइड, एलेनॉर हूम्स नॉर्टन और जीसस गार्सिया ने वाशिगटन स्थित भारतीय दूतावास और अन्य अमेरिकी शहरों के वाणिज्य दूतावासों पर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों की निगरानी के लिए ऑटोग्राफर को तैनात करने का आरोप लगाया है। रुबियो फलेसे स्पताह भारत यात्रा पर जा रहे हैं और मुंबई में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे।

सांसदों ने शुक्रवार को सूबयों की लिख एक पत्र में कहा, "हम दिल्ली और भारत के अन्य क्षेत्रों में छात्रों के प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लेने तथा अत्यधिक बल प्रयोग करने के मुद्दे को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं।" सांसदों ने अपने पत्र में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान को खिलाफ काँजपा के प्रदर्शनों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी प्रदर्शनों का उदाहरण देते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने का हावाला दिया। जयपल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का संदर्भ देते हुए भारत में "मसौदा मतदाता सूची से 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए जाने" पर चिंता जताई और काँकरोच जनता पार्टी को अपराध समर्थन दिया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने जयपल की टिप्पणियों की कड़ी नज़र करते हुए इसे भारत के आंतरिक मामलों में "अस्वीकार्य हस्तक्षेप" करार दिया।



टैरिफ लगा सकें। ट्रम्प ने 18 सितंबर को ग्रेनाडा एक्ट्स पर हस्ताक्षर करके इसे कानून का रूप दिया था। इसका मकसद फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद माँस्को पर रूसी आर्थिक दबाव बढ़ाना था। इसके तहत रूस के ऊर्जा क्षेत्र और रूस से तेल व गैस खरीदने वाले देशों को निशाना बनाया गया था। इस कार्यकारी आदेश के तहत, रूस से आने वाले सामानों पर शुल्क 500 प्रतिशत तक बढ़ सकता था। आदेश में यह भी प्रावधान था कि अगर रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात करने वाले पाँच सबसे बड़े देश 18 अक्टूबर या उसके बाद जानबूझकर रूस से नई खरीदारी करते हैं, तो उनके सामानों पर 100 टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा,

रूस पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ने में मदद करने वाले पांच सबसे बड़े देशों के सामानों पर भी 100% अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कहती गई थी। द्रुम ने अब इन शुल्कों को हटा दिया है। रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में से एक, भारत ने वाशिंगटन को चेतावनी दी थी कि अतिरिक्त टैरिफ लगाने से दोनों देशों के आपसी संबंधों पर असर पड़ सकता है। नई दिल्ली का कहना है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खरीदारी और किफायती आपूर्ति मिल सके। चीन ने भी इन प्रस्तावित उपायों का विरोध किया था।

तेल की कीमते, मध्यावाधि
चुनाव और आलोचना

यह छूट एस समय में दा
गई है जब अमेरिका को ईरान

को लेकर चल रहे संघर्ष के बीच ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। इस नए उपायों को लागू करने से तेल की कीमतों और बढ़ने का खतरा था, जिससे नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिकी उपभोक्ताओं पर दबाव और बढ़ जाता। ट्रम्प को हाल ही में हुए एक समझौते को लेकर भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। इस समझौते के तहत रूस से डीडील के निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, ताकि वैश्विक आपूर्ति बढ़ाई जा सके और ईंधन की कीमतों का कम किया जा सके। आलोचकों (जिनमें कुछ अमेरिकी सीनेटर भी शामिल हैं) का तर्क है कि इस व्यवस्था से माँस्को को यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए फंड जुटाने में मदद मिल सकती है। अमेरिकी प्रतिनिधि डॉन बेयर ने ट्रम्प के हालिया फैसले की आलोचना की। उन्होंने ट्रम्प पर आरोप लगाया कि वे यूक्रेन को कमजोर कर रहे हैं और रूस के आक्रमण के लिए उसे दंडित करने के कांग्रेस के प्रयासों को कमजोर कर रहे हैं।

ऊर्जा सहयोग पर ध्यान केंद्रित हुआ देसी उत्पाद खोजें

अमेरिका में ईंधन की कीमतों को लेकर बना दबाव, विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मुंबई और आगामनार (जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है) की आगामी यात्रा के महत्व को और बढ़ा देता है। नवंबर में होने वाले मध्यवर्षीय चुनावों से पहले डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में, ट्रम्प रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों का मुद्दा और भी अहम हो गया है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने रुबियो की इस यात्रा को घ्यापार पर अधिक केंद्रित बताया है। गुफ्फार को बात करते हुए, गोर ने कहा कि रुबियो मुंबई में कई बैठकें करेंगे। इसके बाद वे जामनगर जाएंगे, जहाँ वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। रिलायंस वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स चलाती है। गोर ने रिलायंस की उस योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत कंपनी 50 वर्षों में अमेरिका में अपनी पहली रिफाइनरी खोलने जा रही है।

यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ट्रम्प प्रशासन एक तरफ घरेलू ऊर्जा चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ रूसी तेल आपूर्ति और प्रतिबंधों को लेकर अपनी नीति तय कर रहा है। इस कार्यकारी आदेश (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर) में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया है कि वे अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर इस बात पर नजर रखें कि विभिन्न देश कितना रूसी तेल और गैस खरीद रहे हैं। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई देश मॉस्को को प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहा है। अधिकारियों को इन घटनाक्रमों की जानकारी राष्ट्रपति को देनी होगी और ऐसी स्थितियों को उजागर करना होगा, जिन पर आगे और कार्रवाई हो सकती है।

यह छूट तब तक लागू रहेगी जब तक कि ट्रम्प या प्रशासन के संबंधित अधिकारी यह तय न कर लें कि आगे और कार्रवाई करना उचित है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इससे रूस की गतिविधियों से जुड़े उद्देश्य प्रतिबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो पहले के कार्यकारी आदेशों के तहत लगाए गए थे।



प्रणाली) की पुष्टि हुई है, जिसे पिछले पांच वर्षों में 180 से अधिक परीक्षणों के जरिए विकसित किया गया था। दक्षिण कोरिया की सेना, जो अक्सर उत्तर कोरिया पर अपनी सैन्य तकनीकों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का आरोप लगाती है, उसने ज़ब्बू की इस रिपोर्ट पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। उत्तर कोरिया ने हाल के हथियारों में हथियारों के प्रदर्शन को तेज कर दिया है। इसमें लगभग तीन वर्षों में पहली बार पानी के भीतर से मिसाइल लॉन्च करने का परीक्षण भी शामिल है। ऐसा लगता है कि नेता किम जोंग-उन ने वर्षों तक बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करने के बाद, अब पञ्चा ध्यान नौसैनिक क्षमताओं की ओर केंद्रित कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बुधवार को किए गए मिसाइल परीक्षणों में संभवतः एक ऐसी पनडुब्बी शामिल थी जिसे अभी तैनात नहीं किया गया है; प्योंगयांग के अनुसार, इसे परमाणु हथियार लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। खबर के अनुसार, परीक्षण में टॉर्पीडो की प्रणोदन प्रणाली की क्षमता की भी पुष्टि हुई। इस प्रणाली को पिछले पांच वर्ष में 180 से अधिक परीक्षणों के जरिए विकसित किया गया है। उत्तर कोरिया पर अक्सर अपनी सैन्य प्रौद्योगिकी की क्षमताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाने वाली दक्षिण कोरिया की सेना ने किसी एनए की रिपोर्ट पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

यमन के अदन के हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों

का मिसाइल हमला, टला बड़ा हादसा

यमन के बंदरगाह शहर अदन के हवाई अड्डे पर शुक्रवार रात को मिसाइलों गिरी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। से भी कम समय में हवाई अड्डे पर यह दूसरा हमला है। पुलिस ने बताया कि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हूती विद्रोहियों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच सऊदी अरब और सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार, दोनों को निशाना बनाया है। अदन में दो दिनों के भीतर यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले, बृहस्पतिवार को हूती विद्रोहियों ने अदन में एक महल परिसर पर हमला किया था, जिसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई थी। इस महल परिसर में सरकार का मुख्यालय है। हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाली समाचार एजेंसी 'सबा' के समूह के एक अज्ञात सैन्य अधिकारी ने बताया कि विद्रोहियों ने हवाई अड्डे से सटे एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि इस ठिकाने पर विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रही सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सेना का अड्डा और हथियारों का भंडार मौजूद है। अधिकारियों के अनुसार, हूती विद्रोहियों ने इससे पहले सात अक्टूबर को भी हवाई अड्डे पर दो मिसाइलों से हमला किया

प्रतापगढ़ ब्यूरो
शरद कुमार श्रीवास्तव
7/31, अचलपुर, प्रतापगढ़

संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल
स्व.श्रीमती साधना
सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव
प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय
संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक
(तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव
विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव



आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से प्रकाशित

शहर समता हिन्दी दैनिक / साप्ताहिक समाचार पत्र

समस्त जनपदों में • तहसील • ब्लॉक / शहर में

भर्ती - निम्न पदों हेतु

- ✓ ब्यूरो प्रमुख
- ✓ चैफ़ रिपोर्टर
- ✓ समावाददाता
- ✓ प्रतिनिधि मण्डल

- समाचार संकलन एवं ब्यूरो संचालन हेतु
- क्षेत्रीय रिपोर्टिंग व समाचार कवरेज हेतु
- स्थानीय समाचार, घटनाओं की रिपोर्टिंग हेतु
- जिला/तहसील/ब्लॉक स्तर पर प्रतिनिधित्व हेतु

आकर्षक वेतन और भत्ते आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

पात्रता एवं विवरण

- पत्रकारिता में उच्च रकने वाले अनुभवी/नवीन दोनों आवेदन कर सकते हैं
- स्थानीय समता की समता और अन्य क्षेत्रों में लोकप्रियता आवश्यक
- तत्काल नज़र के सम्मुख भर्ती प्रक्रिया में मान्यता

संपर्क सूत्र:

☎ 919005239332
☎ 919450482227

संपर्क करें: शहर समता हिन्दी दैनिक / साप्ताहिक समाचार पत्र कार्यालय, प्रयागराज

हमारे साथ जुड़े और पत्रकारिता में बनाएं अपना भविष्य !

याद और दम्पाम के लिए और
हों से आने-जाने वाली उड़ानों
के अस्थायी रूप से निलंबित
कर दिया है। हम समझते हैं कि
इससे हमारे यात्रियों की यात्रा
योजनाओं पर असर पड़ सकता
है और हम इस दौरान उन्हें हर
संभव सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध
हैं। नबन में आगे कहा गया
कि यात्रियों के पास 15 अक्टूबर
2026 या उससे पहले की गई
एयर इंडिया या एयर इंडिया
एक्सप्रेस की कन्फर्म बुकिंग है,
तो जिनकी यात्रा की तारीखें 9
अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 के
बीच हैं, वे 10 नवंबर 2026 तक
अपनी संबंधित एयरलाइन पर एक



बार मुफ्त में यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। जो यात्री अपनी मूल यात्रा योजना के अनुसार किसी दूसरी तारीख पर दोबारा बुकिंग नहीं करना चाहते, वे उपलब्धता के आधार पर ळक्ष क्षेत्र के किसी अन्य स्टेशन से अपनी यात्रा फिर से बुक कर सकते हैं। यात्री पश्चिम एशिया में किसी अन्य गंतव्य को भी चुन सकते हैं। एयरलाइन का कहना है, जो यात्री इस विकल्प को चुनते हैं, उन्हें अपनी पसंद की नई जगह तक पहुँचने के लिए यात्रा का इंतज़ाम खुद करना होगा, और साथ ही वीजा व प्रवेश से जुड़ी जरूरी शर्तों को भी पूरा करना होगा। एयर इंडिया के यात्री दुबई या दोहा के लिए (आने या जाने के लिए) अपनी बुकिंग बदल सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री अबू धाबी, अल ऐन, बहरीन, दोहा, दुबई, कुवैत, मस्कट, रास अल खैमाह, सलालाह या शारजाह के लिए अपनी बुकिंग बदल सकते हैं। जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, वे यात्रा न करने का फैसला लेकर पूरे रिफंड का विकल्प भी चुन सकते हैं। एयर इंडिया ने कहा, ष्म स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और आगे जो भी अपडेट होगा, उसके बारे में यात्रियों को सूचित करते रहेंगे।

यूक्रेन में स्टारलिनक
एक्सेस रुकने पर बोले
डोनाल्ड ट्रंप, एलन
मस्क जिम्मेदार नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यूक्रेन के स्टारलिक एक्सेस खोने के लिए वह या एलन मस्क जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से रूस के खिलाफ यूक्रेन के सैन्य अभियानों में बाधा आई। सैटेलाइट सेवाओं में कटौती के कारण मुख्यालय के साथ संचार बाधित हुआ और इंटरनेट की गति धीमी हो गई। रॉयटर्स ने गुरुवार को रिपोर्ट दी थी कि व्हाइट हाउस ने स्टारशील्ड सेवाओं में कटौती को मंजूरी दी थी। व्हाइट हाउस से जॉर्जिया के लिए रवाना होते समय पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के स्टारशील्ड एक्सेस पर कोई भी प्रतिबंध अमेरिका की ओर से नहीं लगाया गया था।

विशेष रूप से सरकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ग्राहकों, खासकर अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित किया है।